04 - युद्ध और अल नीनो के बीच खड़ी दुनिया

05 - घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता की आवश्यकता

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 16 जून, 2026

06 - वाहन चालक नहीं करते यातायात नियमों का पालन, इसलिए बढ़ रहे...

07 - मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 की समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 284, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

ईरान-अमेरिका डील तो हो गई लेकिन ये खतरे अभी बाकी

एंथनी ज़र्चर

अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी ख़त्म करने के लिए हुए समझौते की घोषणा ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार तोहफ़ा दिया है, हालांकि यह काफ़ी अनिश्चितताओं में लिपटा हुआ है। समझौते का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुल जाएगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा।

ट्रंप ने रविवार को कहा, 'तेल को निर्बाध बहने दो!' उन्होंने आगे कहा कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नाकामियों के उलट उन्होंने एक 'बेहतरीन समझौता' कराया है, जो 'पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा' लाएगा। बेशक, इस तरह की बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातें ट्रंप के लिए नई नहीं हैं।

पिछले साल गाजा युद्ध ख़त्म करने वाले समझौते को लेकर उनके 'हमेशा के लिए शांति' और 'ईमान, उम्मीद और ईश्वरीय शुरुआत' के दावे भी इतने ही बड़े थे, जबकि ज़मीनी हक़ीक़त इन दावों से काफ़ी दूर रही है।

इस तरह के बड़े दांव वाले कूटनीतिक समझौतों में क़ामयाबी या नाकामी आमतौर पर बारीक़ ब्योरों पर निर्भर करती है। और यहां यही ब्योरे बहुत कम उपलब्ध हैं।

तेल की आवाजाही पर अभी भी आशंका: रविवार शाम फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, यह बात 'इस समझौते में शामिल है' और अमेरिका इसके पालन की पुष्टि कर सकेगा।

इनमें से कुछ बातें आगे की बातचीत और मौजूदा युद्धविराम को 60 दिन बढ़ाने के दौरान होने वाली 'तकनीकी' वार्ताओं में तय की जाएंगी।

लेकिन अगर दशकों से ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटाने के लिए किए गए प्रयासों से कुछ साफ़ हुआ है, तो वो यह है कि कोई गारंटी नहीं होती, चाहे अमेरिका को इस 'समझौता एमओयू' में कितना भी भरोसा क्यों न हो। मानो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा, 'अंतिम बातचीत को तब तक टाल दिया जाएगा, जब तक समझौता ज्ञापन के तहत दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया जाता। वे प्रतिबद्धताएं क्या हैं और ईरान उनकी क्या व्याख्या करता है, इससे यह तय होगा कि यह समझौता टिकेगा या नहीं। ऊर्जा बाज़ार के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर पर तुरंत लौटने की संभावना नहीं है।

बड़ी संख्या में फंसे तेल टैंकरों को हटाने, बारूदी सुरंगों को साफ़ करने और सामान्य तेल आपूर्ति व उत्पादन बहाल करने में कई सप्ताह लग सकते हैं।

आधिकारिक हस्ताक्षर होने में अभी कई दिन बाकी हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के पास समझौते की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अहम बिंदुओं पर सहमति बनाने का समय है, लेकिन इसके टूटने की आशंका भी बनी हुई है।

इसराइल का फ़ैक्टर: एक और अनिश्चित फ़ैक्टर इसराइल है। यह हमेशा से तीन पक्षों वाला युद्ध रहा है और ट्रंप ने रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि वह इसराइली प्रधानमंत्री बिन्जामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने इस सप्ताहांत लेबनान में हमले करने का आदेश दिया था। ट्रंप का मानना था कि इससे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका ईरान समझौता पटरी से उतर सकता था। समझौता कायम रहा, कम से कम इतनी देर तक कि इसकी सार्वजनिक घोषणा की जा सके। लेकिन अगर इसराइल लेबनान में नए सैन्य अभियान शुरू करता है, तो ईरान फिर से होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का फ़ैसला कर सकता है और एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को ख़तरे में डाल सकता है।

अपनी टिप्पणी में वेंस ने यह भी माना कि इस युद्ध ने ऊंची ऊर्जा क़ीमतों और उनसे जुड़े आर्थिक असर की वजह से कई अमेरिकियों को परेशान किया है। उन्होंने कहा, 'अमेरिकी लोगों के लिए मेरा मुख्य संदेश है, धन्यवाद।' साथ ही उन्होंने वादा किया कि ईंधन क़ीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी।

ट्रंप को कितना फ़ायदा: तेल के दाम कितनी जल्दी कम होते हैं और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे अमेरिकियों के लिए यह कितनी जल्दी राहत के रूप में दिखाई देता है, इससे काफ़ी हद तक यह तय होगा कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन पार्टी पर बढ़ता दबाव कम होता है या नहीं। हालिया पोल्स के मुताबिक़, ट्रंप और उनकी पार्टी को जनता की बढ़ती नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। यूगोव सर्वे में पाया गया कि 63% अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के उनके तरीक़े से असंतुष्ट हैं, जबकि 57% लोगों का मानना है कि अर्थव्यवस्था और बिगड़ रही है।

कम से कम इतना तो है कि रविवार का समझौता जारी संघर्ष से पैदा हुए कुछ आर्थिक दबाव को कम करने में मदद कर सकता है, भले ही उसे पूरी तरह ख़त्म न कर सके। अगर पेट्रोल की क़ीमतें वास्तव में गिरना शुरू होती हैं, तो यह अमेरिकियों के लिए इस बात का ठोस संकेत हो सकता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं।

यह जंग शुरू होने से पहले जैसी स्थिति थी, उसकी ओर बढ़ाया गया एक अहम क़दम है, भले ही ट्रंप के बड़े लक्ष्य फ़िलहाल पूरे नहीं हुए हों और उन्हें अपने देश में अब भी राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा हो।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

अपनी ग़ज़ल में लाएँ भी तो इंकलाब क्या।
जो लिख दिया तो लिख दिया उसका हिसाब क्या।।
दिल की हरेक बात को हमने बयाँ किया।
अब सोचते रहिएगा कि अच्छा,खराब क्या।।
दिन भर तो साँस लेना भी मुश्क़िल बहुत हुआ।
फिर देखते भी कैसे हसीं कोई ख़्वाब क्या।।
जिसने खुदी गिरेबाँ में झांका नहीं कभी।
मुट्ठी में लेके आएगा वो आफताब क्या।।
हर बार जान लेने पे आमादा हो गया।
लिखकर या उसे बोलकर देता जवाब क्या।।
अच्छा नहीं है हुस्न पर इतना गुमान भी।
मुड़कर भी देखता नहीं,आया शबाब क्या।।
'तन्हा' यूँ ज़िन्दगी से फ़क़त जूझता रहा।
फिर पढ़ता भला कैसे मैं कोई किताब क्या।।

-सलीम तन्हा

प्रदेश में सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना

सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा : सीएम डॉ. यादव

आज डेटा है सबसे मूल्यवान संपत्ति

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। डेटा की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में सायबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हर दिन इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। अपराध के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक तकनीक और द्रोण जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा

चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी का देश की सुरक्षा को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए अभिनंदन है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की विशेषता है कि वह समय से पहले आने वाले वाली चुनौतियों को पहचान लेते हैं और शासन-प्रशासन और जन सामान्य को उसके प्रति जागरूक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम भी उठाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश पर सायबर अपराध, डीप फेक और अन्य चुनौतियों पर केंद्रित कार्यशाला में सायबर सुरक्षा संस्कृति को सशक्त बनाने में सभी मार्ग खोजे जाएंगे।

डीबीटी की पारदर्शी व्यवस्था से हितग्राहियों तक पहुंचने लगा है शत-प्रतिशत लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश बदलते दौर में हर तरह की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सायबर अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की शुरुआत की। जनधन खाते खुलने से देशभर में जरूरतमंदों को डीबीटी के माध्यम से हितलाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाने लगा। डीबीटी की पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से शत प्रतिशत लाभ हितग्राहियों तक पहुंचने लगा। दुनिया ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम का लोहा माना है। ऐसे समय में जब नागरिकों को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से लाभ पहुंच रहा है तो सरकार पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

सायबर क्राइम के अदृश्य खतरों से निपटने के लिये आवश्यक प्रबंधन जरूरी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुरक्षा के तमाम चाक-चौबंद उपायों के बाद भी अगर जीवनभर की गाढ़ी कमाई एक झटके में कोई सायबर अपराधी उड़ा ले जाए तो दुख होता है।

- **सायबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सेंटर-** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सायबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य में सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। सेंटर केंद्रीय सायबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सायबर अटैक की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस सेंटर की महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी।

अमेरिका-ईरान जंग खत्म करने पर हो गए हैं राजी

- 19 जून को हो सकते हैं दस्तखत, होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलेगा

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा।

उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने लिखा, 'दुनिया के जहाजो, अपने इंजन चालू कर लो। तेल को बहने दो।' इधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता

- **ईरान ने दस्तखत करने से पहले 3 शर्तें रखीं-** ईरान-अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका-ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने तीन वादे पूरे करता है या नहीं। गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को तीन कदम उठाने होंगे।

नाबालिग समेत 4 डूबे

युवती का शव मिला

मैहर से सीधी पिकनिक मनाने आए थे, तीन की तलाश, नदी में मौजूद मगर-घड़ियाल

सीधी (एजेंसी)। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी के भंवरसेन घाट पर सोमवार दोपहर पिकनिक मनाने आए चार युवक-युवतियां और नाबालिग डूब गए। इनमें से एक युवती का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। यह घटना मैहर जिले से आए एक परिवार और उनके रिश्तेदारों के साथ हुई।

जानकारी के अनुसार, सभी नदी में नहा रहे थे तभी वे गहरे पानी की चपेट में आ गए और देखते ही देखते डूब गए। इस हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

घटना की सूचना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे मिली। तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष मिश्रा, रामपुर नैकिन थाना पुलिस और खड्डी चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। तलाश अभियान के दौरान, एक युवती का शव घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला।

शव की पहचान ज्योति सेन (24) निवासी बूढ़ा बाउर, थाना रामनगर, जिला मैहर के रूप में हुई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

रेक्स्यू कर रही टीम

तहसीलदार आशीष मिश्रा ने बताया कि बचाव दल को तत्काल बुलाया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम नदी में लापता अन्य तीन लोगों की लगातार तलाश कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि सभी गहरे भंवर में फंस गए थे, जिससे वे बाहर नहीं निकल पाए। नदी के गहरे भंवर और तेज बहाव के कारण यह क्षेत्र खतरनाक माना जाता है। प्रशासन की निगरानी में रेस्क्यू अभियान जारी है।

नाबालिग लड़की समेत ये तीन लापता- हादसे में लापता हुए लोगों में सुभि सेन (15) पिता रामदयाल सेन, नीलू बैस (22) पिता लल्लू बैस (दोनों निवासी बूढ़ा बाउर, जिला मैहर) और लखन केवट (26) पिता मोहनलाल केवट, निवासी घोगटपुर, जिला राजगढ़ शामिल हैं। भंवरसेन घाट पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और स्नान के लिए आते हैं।

तीन घंटे बाद भी नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम- दोपहर करीब 12 बजे घटना घटने 3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक एसडीईआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इसके पहले मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ही एक युवती का शव नदी से बाहर निकाला है। मौजूद परिजन लगातार प्रशासन से टीम भेजने के लिए मोबाइल पर संपर्क साध रहे हैं।

कुछ दिन पहले छोड़े हैं 14 मगर और घड़ियाल

सीधी जिले की सोन नदी का यह वही स्थान है, जहां सोन घड़ियाल अभयारण बनाने की योजना है। यहां 14 मगर और घड़ियाल को छोड़ा था और यहां सेंचुरी बनाने के लिए प्रयासरत है। पांच दिन पहले भी एक तालाब से मगर को रेस्क्यू कर यहां पर छोड़ा था।

अब टिकाऊ और अंतिम समझौते की है उम्मीद

- अमेरिका-ईरान की पीस डील पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होने हैं। इसका दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष खत्म करने के लिए बनी इस सहमति का वह स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुई है और कई देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे लिखा, भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही व व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक टिकाऊ और अंतिम समझौता हो सकेगा।

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता- अमेरिका और ईरान ने तीन महीने से ज्यादा समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की है कि शुक्रवार, 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

...बाकी जो बचा था 'महंगाई' मार गई

- देश में थोक महंगाई 43 महीने में सबसे ज्यादा
- मई में 9.68 फीसदी पहुंची, फ्यूल महंगा हुआ
- अनाज-तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंचीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68 फीसदी पर पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल में यह 8.26 फीसदी पर थी। मई में महंगाई 43 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर 2022 में ये 10.70 फीसदी पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 जून को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और फ्यूल के दाम बढ़ना है। इसके अलावा अनाज और तेल भी महंगा हुआ है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच साढ़े तीन महीने से तनाव है। स्थितियां सामान्य नहीं हुईं तो महंगाई और बढ़ सकती है।

रोजाना जरूरत के सामान, फ्यूल और पावर के दाम बढ़े

रोजाना की जरूरत वाले सामानों (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 3.78 से बढ़कर 4.99 फीसदी हो गई। खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई 3.11 से बढ़कर 4.49 फीसदी पर पहुंच गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 24.89 से बढ़कर 30.33 फीसदी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 6.68 से बढ़कर 7.48 फीसदी रही। प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज 22.62 फीसदी है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15 फीसदी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा 64.23 फीसदी है। प्राइमरी आर्टिकल के भी चार हिस्से हैं। मई में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.93 फीसदी पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 3.48 फीसदी थी। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट 4 फीसदी के बेहद करीब पहुंच गई है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 16 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

दूसरा भाई होता तो उसे भी आर्मी में भेज देती

असम एएन-32 हादसे के शहीद प्रशांत सिंह की बहन का जज्बा

देहरादून (एजेंसी)। असम के जोरहाट में एयरफोर्स का एएन-32 विमान क्रैश हादसे में देहरादून के प्रशांत सिंह शहीद हो गए हैं। हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर की बहन निवेदिता सिंह का कहना है कि इस हादसे के बाद हमारी

जिंदगी में एक ऐसी कमी आ गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरा दूसरा भाई भी होता तो उसे भी सेना ज्वाइन करने की सलाह देती। निवेदिता ने कहा कि भले ही यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर भी, मैं युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है।

खान सर ने कराई है मेरे भाई प्रिंस यादव की हत्या

जेल से निकलते ही रौशन आनंद का बड़ा दावा

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में मारपीट फायरिंग के केस में नया मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार ज्ञान

बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद सर बेऊर जेल से बेल मिलने के बाद बाहर निकले। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक नया नाम लिया है। खान सर उर्फ फैजल खान के अलावा वो नाम है किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक का। रौशन आनंद ने जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने दावा किया है कि खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले जीनानी कम्पनी के पदाधिकारी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सोमवार को मंत्रालय में बंगलुरू बेस्ड जीनानी डॉट एआई कम्पनी के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। कम्पनी पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (आईटी सेक्टर)

में निवेश करने की मंशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कम्पनी पदाधिकारियों से कहा कि वे निवेश के संदर्भ में ठोस परियोजना प्रस्ताव और स्पष्ट रोडमैप लेकर आएं, सरकार कम्पनी की सभी प्रकार की मदद करेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री एम सेलवेंद्रम, जीनानी डॉट एआई कम्पनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री अनंत नागाराज, कम्पनी के हेड ऑफ एआई ट्रांसफार्मेशन (पब्लिक सेक्टर) कर्नल आदिश वाबुमकर (रिटायर्ड) भी उपस्थित थे।

गायब हो गए बदरा, सैटेलाइट तस्वीरों में भी नहीं आ रहे नजर

● एमपी-राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार और बढ़ा ● 4 से 15 जून के बीच 64 फीसदी कम हुई बरसात, संकट बढ़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक, 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिमी के मुकाबले सिर्फ 19.2 मिमी बारिश हुई। यानी बारिश में 64 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रुक गया है।

हवाओं के बदले पैटर्न से धीमा पड़ा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के कमजोर होने की वजह समुद्र में नमी की कमी नहीं, बल्कि ऊपरी वायुमंडल की हवाओं का असामान्य पैटर्न है। इस बार पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य से ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है, जिससे मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं प्रभावित हो रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त नमी के बावजूद बादल नहीं बन पा रहे हैं।

इससे मानसून के आगे बढ़ने पर फिलहाल ब्रेक लग सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री-मानसून बारिश जारी है।

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 17 जून तक हीटवेव

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 17 जून तक लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, मराठवाड़ा में 17 जून तक और विदर्भ में 16 जून तक हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में 17 जून तक गर्मी के साथ उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में 16 जून तक रात में भी गर्मी से बनी रहेगी।

सभी समाजों को, उनकी परम्पराओं को जोड़ें, आल्हा-ऊदल स्मृति उत्सव और श्रावण महोत्सव भी मनायें : मुख्यमंत्री

संस्कृति विभाग की करें पुनर्संरचना, गतिविधियों का भी करें विस्तार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी छह-सात माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनायें जायेंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को, उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करें। आल्हा-ऊदल वीर रस गायन के प्रतीक हैं, उनकी स्मृति में आयोजन किए जाएं। श्रावण महोत्सव और भुजरिया पर्व भी मनाएं। नागपंचमी पर जैव विविधता संरक्षण (सर्प प्रजातियों के संरक्षण) का संदेश दिया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति विभाग लोगों को जोड़कर ऐसे आयोजन करें, जिनसे हमारी कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ ही सरकार के संदेश का भी प्रसार हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति, परम्पराएं और समृद्ध पुरातात्विक धरोहरें प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं, जिन्हें संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध और प्रभावी प्रयास किए जाएं। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए हमारी सरकार हर जरूरी प्रयास कर रही है। हम समाज को साथ लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किये गये 'कला पंचांग' का विमोचन भी किया। इसमें विभाग द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कलात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है। अब इन्हें सिलसिलेवार क्रियान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का दायरा और तेजी से बढ़ेगा। विभागीय आंतरिक विशेषताओं और विशेषज्ञताओं का समुचित संयोजन करते हुए संस्कृति विभाग की और बेहतर पुनर्संरचना की जाये।

विभागीय गतिविधियों का आधुनिक संदर्भों में विस्तार भी किया जाये। उन्होंने कहा कि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग सभी मिलकर काम करें, ताकि प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे प्रदेश में उत्कृष्ट कारीगरी से निर्मित होने वाले क्रॉफ्ट आइटम्स, हैंडलूम आइटम्स और कशीदाकारी को भी पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट वीर विक्रमादित्य के नाम से एक पृथक अकादमी का गठन किया जाये। इसमें विक्रमादित्य के जीवनवृत्त पर समग्र शोध एवं अन्य संगत गतिविधियां भी संचालित की जायें।

साहित्यकार बहनों ने लिया वृक्षारोपण का संकल्प

भोपाल। हिन्दी लेखिका संघ, म.प्र. भोपाल द्वारा सोमवार को शिवाजी नगर स्थित विश्व संवाद केन्द्र के सभागार में 'पर्यावरण' विषय पर काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में 50 साहित्यकार बहनों ने पर्यावरण संरक्षण, अपनी दैनिक जीवनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण का संकल्प लिया।

गोष्ठी में शहर की प्रबुद्ध लेखिकाओं एवं कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, घटते वन क्षेत्र, पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। कविताओं में प्रकृति के प्रति मनुष्य के दायित्व तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित भविष्य सुनिश्चित करने का संदेश प्रमुखता से उभरकर सामने आया।

संस्था की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने स्वागत उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए साहित्यकारों से जनजागरण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से अपनी आयु के बराबर वृक्ष आगामी दस वर्षों में लगाने का संकल्प लेने की अपील भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं पर्यावरणविद् श्रीमती सीमा वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवनशैली में परिवर्तन आवश्यक है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पर्यावरणविद् श्रीराम माहेश्वरी ने वृक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य बताया।

विशिष्ट अतिथि एवं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी जगदीश चन्द्रा ने वन एवं वन्यजीवन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी कविता 'अगर वृक्ष बोल पाता' का पाठ कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया।

काव्य गोष्ठी में नीलिमा रंजन, मनोरमा श्रीवास्तव, डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव, सुधा दुबे, कल्पना विजयवर्गीय, वंदना त्रिपाठी, डॉ. सीमा अग्रवाल, बिंदु त्रिपाठी, आशा सक्सेना, डॉ. रेखा भटनागर, कमल चंद्रा, बलजीत सलूजा, नीता श्रीवास्तव 'श्रद्धा', साधना शुक्ला, वंदना गुप्ता, किरण खोड़के, मृदुल त्यागी, मधुलता शर्मा, चित्रा चतुर्वेदी तथा सरोजलता सोनी सहित अनेक कवयित्रियों ने पर्यावरण विषयक रचनाओं का प्रभावशाली पाठ किया।

टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय

● 3 साल पहले पति-पत्नी ने यह पार्टी बनाई थी; नारा था-दलबदलू नेताओं को नकारो

कोलकाता/नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया चर्चा में है। रिकॉर्ड के अनुसार, 3 साल पहले 2023 में बंगाल के उत्तिया कुंडू और शेउली कुंडू नाम के कपल ने पार्टी की नींव रखी थी। पार्टी के डॉक्यूमेंट्स में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं। पत्नी शेउली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है। एनसीपीआई अध्यक्ष उत्तिया ने 13 मई को फेसबुक पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हावड़ा में एनसीपीआई का ऑफिस है, जहां सोमवार को सुरक्षाबलों की तैनाती दिखी। ऑफिस के

गेट पर उत्तिया ने खुद को बंगाली न्यूजपेपर का एडीटर और टीचर बताया है। वहीं उनकी पत्नी शेउली को कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील बताया गया है।

त्रिपुरा चुनाव के बाद गायब हो गई थी पार्टी- न्यूज एजेंसी के अनुसार, एनसीपीआई ने 2023 में त्रिपुरा के चावामानु से बरजेडा त्रिपुरा को उम्मीदवार बनाया था। बरजेडा को 536 वोट मिले थे। टीएमसी के बागी सांसदों के साथ विलय की बात सुनकर वे हैरान रह गए। बरजेडा ने बताया कि वे दिहाड़ी मजदूर हैं। चुनाव के बाद उनका पार्टी से संपर्क खत्म हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा के कैलाशहर से एनसीपीआई उम्मीदवार रहे जहांगीर अली ने बताया कि 2023 चुनाव के दौरान शेउली कुंडू कोलकाता से आई थीं और उम्मीदवारों से संपर्क किया था। चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी ने गतिविधियां बंद कर दीं और संपर्क भी टूट गया। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने रविवार को त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय की घोषणा की। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसद काकोली घोष ने जानकारी दी।

एनसीपीआई बंगाल में रजिस्टर्ड, त्रिपुरा से चुनावी शुरुआत की

एनसीपीआई का रजिस्टर्ड पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बानीपुर इलाके में है। पार्टी ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में चार उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन उसके उम्मीदवार या तो टीएमसी से पीछे रहे या फिर उससे थोड़ा ज्यादा वोट हासिल कर पाए। पार्टी को कुल मिलाकर लगभग 1,198 वोट मिले थे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी को कुल 1.13 लाख का चंदा मिला था। इनके चुनावी पोस्टरों में नारा था- अपने अधिकारों को बचाने के लिए दलबदलुओं को नकारें।

● राम मंदिर के चढ़ावे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई से जांच कराने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे में मिली कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका

दायर की गई है। इस याचिका में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच करने की मांग की गई है। याचिका में एडवोकेट अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस दान में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से अदालत की निगरानी में इसकी जांच करने का निर्देश देने पर विचार करे। याचिका में भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा करने, मंदिर के फंड का कलेक्शन, अकाउंटिंग और खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी तंत्र बनाने की भी मांग की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी चर्चा हुई है। इस मामले में नेताओं के साथ ही साधु-संतों के बयान भी आए हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस पर तंज कसा है।

जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी: मिश्रा

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सोमवार को कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की दान राशि में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी के द्वारा कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग करेगा और एसआईटी को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने रविवार को जिला प्रशासन से भी बातचीत की थी और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इन आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी।

केरल में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना शुरू

● सांसद केसी वेणुगोपाल ने की यूडीएफ सरकार की तारीफ

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोमवार को महिलाओं के लिए राज्य की मुफ्त बस यात्रा योजना का उद्घाटन किया। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ घोषणापत्र का एक अहम वादा था। थम्पानूर सेंट्रल बस टर्मिनल पर हुए लॉन्च इवेंट में भारी भीड़ जुटी। इसमें सीनियर मंत्री, बड़े अधिकारी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लीडर शामिल हुए। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पद संभालने के एक महीने के भीतर ही यूडीएफ ने अपनी पहली इंदिरा गारंटी लागू कर दी है! बहुप्रतीक्षित प्रियदर्शिनी फ्री बस स्कीम अब लागू हो गई है! पूरे केरल में महिलाएं बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी और हर महीने हजारों रुपये बचा सकेंगी! हम जन-कल्याण में विश्वास रखते हैं और हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या अब केरल! फ्री बस योजना चालू है।

भोपाल-जबलपुर समेत 28 जिलों में बारिश

सीहोर में 61 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली; कहीं तेज तो कहीं हल्का पानी गिरा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून से पहले आंधी-बारिश का दौर जारी है। सोमवार को सीहोर में दोपहर 12 बजे के बाद बादल छाए, तेज आंधी चली। मौसम केंद्र ने भोपाल और ग्वालियर में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगर-मालवा और राजगढ़ में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 28 जिलों में आंधी-बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, खरगोन, देवास, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, जबलपुर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, आगर-मालवा में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर, प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में तेज आंधी चली। सीहोर में आंधी की रफ्तार सबसे ज्यादा 61 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। सागर-गुना में 59 किमी, भोपाल में 57 किमी, जबलपुर में 50 किमी, नर्मदापुरम में 48 किमी, इंदौर-अशोकनगर में 44 किमी, ग्वालियर में 43 किमी, राजगढ़ में 39 किमी, आगर-मालवा, रीवा, खंडवा-बड़वानी में 37 किमी, धार में 35 किमी, विदिशा-उज्जैन में 31 किमी और मंदसौर में 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली।

भोपाल में दिनभर बारिश...पारा लुढ़का, शिवपुरी में 33.2 डिग्री पहुंचा

प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश वाला मौसम रहा। भोपाल में रुक-रुककर पूरे दिन बारिश हुई। सीहोर, इंदौर, रायसेन और खरगोन में भी अच्छी बारिश हुई। कई इलाकों में तेज हवाओं से बिजली गुल हो गई, जबकि रायसेन में मकानों के छप्पर उड़ गए। खरगोन में निंदाई और बुआई का काम प्रभावित हुआ। आंधी-बारिश की वजह से दिन के तापमान में खासी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 बड़े शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा है। भोपाल में 35.4 डिग्री, इंदौर में 36.3 डिग्री, ग्वालियर में 39.2 डिग्री, उज्जैन में 36.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

पीसीसी के सामने युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

गिने-चुने 7 कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, मीनाक्षी का नॉमिनेशन खारिज होने का किया विरोध

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर मचे सियासी घमासान के बीच भोपाल में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। शीर्ष नेतृत्व की ओर से भाजपा कार्यालय के घेराव का बड़ा फरमान जारी हुआ था, लेकिन जमीन पर इसकी हवा निकल गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए महज 7 युवा कांग्रेसी ही जुटे, जिन्होंने आनन-फानन में पुतला दहन कर अपनी औपचारिकता पूरी की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (पीसीसी) के सामने सोमवार को नजारा कुछ ऐसा था कि प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेसियों से कई गुना ज्यादा वहां पुलिसकर्मी मुस्तैद खड़े थे। कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी कम यानी महज 'गिनती' की थी कि पुलिस ने भी उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई और न ही उनके हाथ से पुतला छीनने का कोई प्रयास किया। बेहद कम संख्या में मौजूद इन कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया।

प्रदेश संगठन प्रभारी ने जारी किया था पत्र- चौंकाने वाली बात यह है कि 12 जून को एमपी

कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने एक पत्र जारी कर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से खारिज किए जाने के मामले में बड़ा आंदोलन खड़ा करने के निर्देश दिए थे। पत्र में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस को एकजुट होकर 15, 16 और 17 जून को भाजपा कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन करने को कहा गया था, लेकिन संगठन के इस बड़े आदेश के बावजूद भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और पीसीसी के सामने ही प्रदर्शन निपटा दिया।

इसके बावजूद भोपाल शहर युवा कांग्रेस ने बकायदा एक समाचार विज्ञप्ति जारी कर इसे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तानाशाही के खिलाफ बड़ा संघर्ष करार दिया। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस और भोपाल जिलाध्यक्ष अमित खत्री के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला महासचिव अनीस शर्मा ने किया।

पुतला दहन में ये 7 चेहरे आए नजर

पुतला दहन करने वाले 7 चेहरों में जिला उपाध्यक्ष नीरज यादव, महासचिव दर्शन कोरी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन रुडेले, भूपेंद्र मिश्रा, रिजूल सेन और सुजल शामिल रहे, जो मैदान में डटे दिखे। भले ही सड़क पर कार्यकर्ताओं का टोटा दिखा, लेकिन कागजों पर भोपाल युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमित खत्री ने बड़ी हुंकार भरी।

उन्होंने अपना आधिकारिक बयान जारी कर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान की सरेआम हत्या है। यह कृत्य पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर सत्ताधारी दल का राजनीतिक औजार बन चुका है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। खत्री ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई अब देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है।

घर में घुसे मनचलों ने छात्रा से की छेड़छाड़

भोपाल में कोचिंग आते-जाते किशोरी का पीछा करते थे आरोपी

भोपाल (नप्र)। गौतम नगर इलाके में रहने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी लंबे समय से पीड़िता का कोचिंग आते और जाते समय पीछा करते थे। दोनों युवक छात्रा के मोहल्ले में रहते हैं और रविवार को परिजनों की गौर मौजूदगी में उसके घर में घुस गए। जहां आरोपियों ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। परिजनों के लौटने पर लड़की ने मामले की जानकारी दी और उनके साथ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा दी। फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। गौतम नगर पुलिस के अनुसार 17 साल की किशोरी थाना क्षेत्र में रहती है। वह 10वीं कक्षा की छात्रा है और घर के पास ही कोचिंग क्लासेस भी जाती है। घर से कोचिंग के बीच के रास्ते में दो युवक व उसके साथी छात्रा का पीछा करते हुए फब्तियां कसते थे।

पीड़िता ने कई बार बदला रास्ता

परेशान होकर छात्रा ने कई बार रास्ता बदला लेकिन युवक उसे परेशान करते रहे। रविवार दोपहर दोनों युवक पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। वे दोस्ती करने का दबाव डाल रहे थे। छात्रा ने जब बात करने से मना कर दिया तो दोनों युवक अपने साथियों के साथ छात्रा के घर में घुस गए तथा छेड़खानी शुरू कर दी।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस- छात्रा ने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकले। परिजनों के आते ही छात्रा ने पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद छात्रा ने थाने में जाकर मामले की शिकायत कर दी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

'अजमेर-शरीफ पर चादर चढ़ाने के बाद पूजा स्वीकार नहीं होती'

भोपाल में देवकीनंदन ठाकुर बोले-रात में होने वाले विवाह दैत्य परंपरा का हिस्सा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रुद्राक्ष किंग्सटन परिसर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धार्मिक आस्था, पूजा-पद्धति और विवाह परंपराओं को लेकर कई बयान दिए। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जिनकी पूजा सनातन धर्म में पूजनीय नहीं मानी गई है, उनकी आराधना करने से परिवार में संकट उत्पन्न हो सकते हैं। उनके इस बयान पर कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी प्रतिक्रिया दी।

अपूज्य की पूजा से घर में आते हैं संकट- देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं। उन्होंने कहा कि जो पूजने योग्य नहीं हैं, उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक हानि होती है। उनके अनुसार, शास्त्रों में पूजनीय और अपूज्य के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है, जिसका पालन करना आवश्यक है। भोपाल के रुद्राक्ष किंग्सटन परिसर, अपोलो हॉस्पिटल के पास, वार्डिया कला क्षेत्र में सात दिवसीय (13 से 19 जून 2026 तक) श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।

अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने का किया जिक्र- कथा के दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के बाद अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने के बाद देवता उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्थान पर श्रद्धा व्यक्त की, जो उनके अनुसार पूजनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का केंद्र शास्त्र सम्मत होना चाहिए।

बच्चों को कथा में लाने की दी सलाह- देवकीनंदन ठाकुर ने अभिभावकों से बच्चों को भी कथा और धार्मिक आयोजनों में साथ लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार जो बातें बड़े लोगों को समझ में नहीं आतीं, वे बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। उनके अनुसार संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही किया जाना चाहिए।

रात में होने वाले विवाहों पर उठाए सवाल- कथावाचक ने आधुनिक विवाह परंपराओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में विवाह गोधूलि बेला में संपन्न कराने की परंपरा थी, जबकि वर्तमान में अधिकांश विवाह देर रात आयोजित किए जाते हैं। उनके अनुसार, रात्रि का समय विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है और इस कारण वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका रहती है।

रात्रि विवाह से बढ़ते हैं पति-पत्नी के विवाद- देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि दिन और रात की परंपराओं को देव और दैत्य प्रवृत्तियों से जोड़कर देखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विवाह रात में होने के कारण पति-पत्नी के बीच टकराव और विवाद बढ़ते हैं।

संघ शताब्दी वर्ष

मध्य भारत प्रांत में शाखाओं की संख्या बढ़कर 3957 हुई, अब 5000 का लक्ष्य

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मध्य भारत प्रांत की दो दिवसीय बैठक भोपाल के शारदा विहार में संपन्न हुई। प्रांत कार्यवाह हेमंत सेठिया ने बताया कि शताब्दी वर्ष में संघ कार्य को और गति मिली है।

प्रांत में शाखाओं की संख्या पिछले वर्ष के 3674 से बढ़कर अब 3957 हो गई है और आगामी वर्ष तक 5000 से अधिक शाखाएं लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में कुल 1730 मंडल संघ कार्य युक्त हैं।

बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि व्यापक गृह संपर्क अभियान के तहत 80 हजार स्वयंसेवकों ने 27 लाख 46 हजार से अधिक घरों तक दस्तक दी।

वहीं, मंडल-बस्ती स्तर पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों में लगभग 52 लाख नागरिक शामिल हुए, जिनमें मातृशक्ति की संख्या 27 लाख से अधिक रही। इसके अलावा प्रांत में सेवा कार्यों की संख्या भी 2448 से बढ़कर 3100 हो गई है। समापन सत्र में सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि शताब्दी वर्ष के बाद अब हमें मंडल और बस्ती की इकाइयों को और अधिक सक्षम बनाना है। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध और नागरिक अनुशासन जैसे पंच परिवर्तन के विषयों को समाज व्यापी बनाने का आह्वान किया। बैठक में प्रांत संघचालक अशोक पांडेय सहित करीब 514 प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्मार्ट सिटी पार्क में छात्र से चाकू अड़ाकर लूट

नकदी और ईयरफोन छीना, यूपीआई से भी 1200 रुपए ट्रांसफर कराए, दो गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में बैठे एक छात्र के साथ दो बदमाशों ने चाकू अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले छात्र के साथ मारपीट की, फिर उसकी जेब से नकदी और ईयरफोन छीन लिया।

इसके बाद फोन-पे के जरिए भी रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार की रात की है। जबकि एफआईआर तड़के सुबह दर्ज की गई है।

श्यामला हिल्स थाना प्रभारी नीलम पटवा के मुताबिक 23 वर्षीय दीपू यादव एक निजी कॉलेज का छात्र है। वह अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में बैठा हुआ था। इसी दौरान दो युवक हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचे। खतरा देखते हुए छात्र ने अपनी दोस्त को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने छात्र को घेर लिया और चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी जेब में रखे करीब 2 हजार रुपए, ईयरफोन छीन लिए। इतना ही नहीं, धमकाकर छात्र के मोबाइल से फोन-पे के माध्यम से करीब 1200 रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।

आरोपियों की पहचान कर 12 घंटे के भीतर पकड़ा- वारदात के बाद छात्र थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों का हुलिया लेकर तलाश शुरू की। जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान कृष्णा और रितिक के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।

नगरीय निकाय एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे-आपत्ति 25 जून तक लिये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जायेगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है ।

राजा भोज एयरपोर्ट पर लगेगा हाईटेक एमएसएसआर रडार

हवा में नहीं टकराएंगे विमान, पलक झपकते ही होगी पहचान

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की सुरक्षा और विमानों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यहां अत्याधुनिक मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस नई तकनीक के आने से न सिर्फ विमानों की पहचान तेजी से हो सकेगी, बल्कि सेंट्रल इंडिया के इस प्रमुख हवाई हब पर एयर ट्रैफिक सेफ्टी भी पहले से कई गुना मजबूत हो जाएगी।

सितंबर तक शुरू हो जाएगी सेवा

यह नया रडार सिस्टम एयरपोर्ट के पुराने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि इस रडार की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है और इसे आगामी सितंबर तक पूरी तरह से कमीशन कर दिया जाएगा। वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे पुराने सिस्टम की तुलना में एमएसएसआर रडार विमानों की स्थिति और उनकी पहचान से जुड़ा बेहद सटीक डेटा देने में सक्षम है। राजा भोज एयरपोर्ट पर एमएसएसआर तकनीक की शुरुआत सर्विलांस क्षमता और यात्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक समय पर उठाया गया कदम है। यह रीयल-टाइम डेटा भविष्य में ऑटोमेशन और एडवांस सर्विलांस टूल्स को अपनाने का रास्ता साफ करेगा, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।

हवाई दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम

एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुसार, रडार से मिलने वाली सटीक जानकारी की मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आसमान की वास्तविक स्थिति समझने में आसानी होगी। किसी भी आपातकालीन या असामान्य स्थिति में प्रतिक्रिया देने का समय घटेगा और विमानों की गलत पहचान का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, यह रडार कोलिजन-अवॉयडेंस (विमानों को आपस में टकराने से रोकने) और पड़ोसी एयरस्पेस के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा।

डीजीपी बोले, प्रदेश में एक लाख एआई बेस्ड कैमरे लगाकर अलग-अलग काम में करें उपयोग

सीसीटीवी कैमरे दिखावा बनकर न रहें, एक्टिव रखे जाएं

भोपाल (नप्र)। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा है कि जिलों में लगाए गए सीसीटीवी दिखावटी बन कर न रहें, उनको चालू रखा जाए और अपराध नियंत्रण में उपयोग किया जाए। एआई बेस्ड एक लाख कैमरे प्रदेश भर में लगाए जाकर उनका उपयोग अलग-अलग प्रबंधन में किया जाए।

इसके साथ ही पुलिस अमले के स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर भी अधिकारी गंभीरता से काम करें। विभागीय जांच और कोर्ट के मामलों के निराकरण में हीला हवाली करने के बजाय इसे तेजी से निपटाया जाए ताकि समय पर लाभ मिल सके।

डीजीपी मकवाणा ने ये बातें पुलिस मुख्यालय में हुई जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक तथा विशेष सशस्त्र बल (विसबल) जोन की दो दिवसीय समीक्षा बैठक के समापन बैठक कार्यक्रम में कहीं।

पुलिस महानिदेशक मकवाणा ने इस मौके पर प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग, प्रशासनिक दक्षता एवं जवाबदेही तय करने को लेकर कहा कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार प्रदान किया जाना है, उनके प्रकरणों

का समयबद्ध निराकरण कर दायित्व सौंपे जाएं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति आए और कर्मचारियों का मनोबल बढ़े।

कोर्ट के पेंडिंग मामलों का जल्द निराकरण करें- डीजीपी मकवाणा ने सभी इकाइयों को लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित एवं प्रभावी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, अवमानना याचिकाओं, सेवा संबंधी मामलों, रिट याचिकाओं तथा स्थगन आदेशों की स्थिति की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सतत निगरानी की जाए तथा समय-सीमा में जवाब दावा एवं आवश्यक अभिमत पेश कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

विभागीय जांच जल्द पूरी करें, पुलिस अमले को प्रोत्साहित करें- डीजीपी ने पुलिस विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली के शत-प्रतिशत उपयोग पर विशेष बल देते हुए निर्देशित किया कि सभी कार्यालयीन कार्यों को अधिकतम रूप से डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाए। स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किए जाने की प्रक्रिया भी समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

डीजीपी ने विभागीय जांच प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने तथा उनके नाम विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों, विशेषकर के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों को पहचान और सम्मान मिलना आवश्यक है, जिससे पुलिस बल में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं कार्य संस्कृति विकसित हो सके।

पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच पर फोकस करें, सिविल सर्जन के साथ हर माह मीटिंग करें एसपी- डीजीपी ने निर्देशित किया कि हर जिले में पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण हेतु जिला पुलिस अधीक्षक प्रतिमाह सिविल सर्जन के साथ बैठक आयोजित करें।

संपादकीय

पाक नहीं कतर!

यह बात उजागर हो गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित समझौते में असल भूमिका कतर की रही है, न कि पाकिस्तान की। जबकि इस मामले में आधिकारिक मध्यस्थ की भूमिका अब तक पाकिस्तान निभा रहा था। ऐसे में दो सवाल उठ रहे हैं, पहला तो यह कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को इस पूरे प्रकरण में डमी की तरह इस्तेमाल किया और दूसरा यह कि इस समूचे मामले में भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कतर की पर्दे के पीछे की अहम भूमिका को बल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि कतर तारीफ का हकदार है और उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए। इस समझौते में कतर ने हमारी बहुत मदद की। हमें यह समझना होगा कि कतर किसी भी दूसरे देश, यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हर चीज के केंद्र में है। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात की पुष्टि की। ट्रंप ने घोषणा की कि इस शुक्रवार को ईरान के साथ किए गये एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में बीते 100 दिन से चल रहे युद्ध के बाद स्थायी संघर्ष विराम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उधर तेहरान ने भी इस घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा है कि युद्ध जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बाद शुरू हुआ था उसे सोमवार सुबह से खत्म कर दिया जाएगा। वैसे खाड़ी देश कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। लेकिन बातचीत के दूसरे दौर के बीच ही ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में परस्पर विश्वास कितना कायम रहता है, यह देखने की बात है। वैसे समझौते की खास बात यह भी है कि आगे दोनो देशों के बीच बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी, न कि पाकिस्तान में। ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने पुष्टि की कि सैन्य अभियानों के जल्द खत्म होने की उम्मीद है।

गरीबाबादी ने कहा कि सोमवार से लेबनान सहित विभिन्न मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा की जाएगी। अंतिम समझौते पर बातचीत 60 दिनों की अवधि के दौरान होगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान यह पुष्टि करे कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे कर लिए हैं। इन वादों में दुश्मनी खत्म करना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में दम नहीं था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा सके। लिहाजा यह काम कतर को संभालना पड़ा। यह बात अलग है कि अमेरिका ईरान विवाद के बीच पाक के कर्णधारों ने अपने मतलब साध लिए। यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वो खास हैं। जबकि दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर खामोश हैं। जानकारों का कहना है कि भारत को अब अपनी पश्चिम एशिया नीति पर बदले हालात में पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि हाल के समय जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले पर चुप्पी बनाए रखना, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर चार दिनों के बाद चुप्पी तोड़ना या फिर कई एक्सपर्ट्स ने मध्यस्थता की कोशिश से भी दूर रहना और भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन नाविकों की मौत के मामले में भी सख्त रवैया न अपनाने पर कई सवाल उठ रहे हैं।

सवालों के घेरे में चुनावी प्रक्रिया की साख

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति हैं। करोड़ों मतदाताओं वाले इस विशाल देश में चुनाव कराना एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी चुनौती का समाधान खोजते हुए भारत ने ईवीएम को अपनाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सरल, तेज और निष्पक्ष बनाना था। मतपत्रों के युग में बूथ कैप्चरिंग, मतपत्रों की लूट, फर्जी मतदान और मतगणना में लंबा समय जैसी अनेक समस्याएं थीं। ईवीएम ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया और चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया। आज भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया के अनेक देशों के लिए अध्ययन और अनुकरण का विषय है। इसके बावजूद ईवीएम को लेकर संदेह और विवाद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए।

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक सरकारी भवन में आग लगने से हजारों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के नष्ट होने की घटना ने देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यद्यपि प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार ये मशीनें मतदान में प्रयुक्त हो चुकी थीं अथवा भंडारण में रखी गई थीं, फिर भी घटना ने राजनीतिक दलों, मतदाताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच अविश्वास की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश में चुनावी पारदर्शिता, ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदाता सूचियों की शुद्धता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे मुद्दे पहले से ही राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि नागरिकों के उस विश्वास का भी नाम है कि उनकी इच्छा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शासन व्यवस्था तक पहुंचेगी। जब चुनावी संसाधनों की सुरक्षा में कोई चूक दिखाई देती है, तब यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर प्रश्नचिह्न बन जाती है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति हैं। करोड़ों मतदाताओं वाले इस विशाल देश में चुनाव कराना एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी चुनौती का समाधान खोजते हुए भारत ने ईवीएम को अपनाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सरल, तेज और निष्पक्ष बनाना था। मतपत्रों के युग में बूथ कैप्चरिंग, मतपत्रों की लूट, फर्जी मतदान और मतगणना में लंबा समय जैसी अनेक समस्याएं थीं। ईवीएम ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया और चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया। आज भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया के अनेक देशों के लिए अध्ययन और अनुकरण का विषय है। इसके बावजूद ईवीएम को लेकर संदेह और विवाद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते रहे हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि जब कोई दल चुनाव जीतता है तो वह ईवीएम की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, जबकि हार की स्थिति में उसी प्रणाली पर प्रश्न खड़े करने लगता है। हालांकि यह भी सच है कि लोकतंत्र में संदेह उठाना किसी भी नागरिक या राजनीतिक दल का अधिकार है। प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देना संस्थाओं की जिम्मेदारी है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब संदेहों का निराकरण करने के बजाय उन्हें अनदेखा किया जाता है या अस्पष्टता बनी रहती है।

पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने की घटना इसी संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हजारों मशीनें एक ही स्थान पर रखी गई थीं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी? यदि वे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में थीं, तो आग वहां तक कैसे पहुंची? क्या आग केवल दुर्घटना थी या सुरक्षा मानकों में कोई गंभीर चूक हुई? इन प्रश्नों का उत्तर केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनकी निष्पक्षता से नहीं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता से भी निर्मित होती है। यहां यह समझना आवश्यक है कि ईवीएम का विवाद केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक भी है। चुनावों में हार-जीत के साथ भावनाएं, अपेक्षाएं और राजनीतिक हित जुड़े होते हैं। यदि मतदाता या राजनीतिक दल यह महसूस करने लगें कि चुनावी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण नहीं है या प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, तो लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए चुनाव आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है।

ईवीएम के समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्तमान ईवीएम इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होतीं, इसलिए दूरस्थ हैकिंग की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त वीवीपैट प्रणाली लागू होने के बाद मतदाता अपने वोट की पुष्टि भी कर सकता है। विभिन्न चुनावों में वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम परिणामों के मिलान में भी बड़े स्तर पर कोई गंभीर विसंगति सामने नहीं आई है। इन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग लगातार यह दावा करता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि केवल तकनीकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती। मशीनों के भंडारण, परिवहन, रखरखाव और निगरानी की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक होती है, यदि स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी पर प्रश्न उठते हैं, यदि मतदाता सूची में त्रुटियां दिखाई देती हैं या यदि चुनावी प्रक्रिया के किसी चरण में पारदर्शिता की कमी महसूस होती है, तो संदेह स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की घटना ने इसी चिंता को पुनर्जीवित किया है कि चुनावी संसाधनों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है।

इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण आयाम चुनाव आयोग की भूमिका भी है। भारतीय चुनाव आयोग को संविधान ने एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था के रूप में स्थापित किया है। उसकी निष्पक्षता पर ही चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता टिकी हुई है। जब भी चुनावों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब सबसे पहले जनता की नजर चुनाव आयोग पर जाती है। ऐसी स्थिति में आयोग का दायित्व केवल जांच करवाना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना भी है। पारदर्शी जांच, समयबद्ध रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को तथ्यात्मक आधार पर परखा जा सके। लोकतंत्र में विश्वास की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या तकनीक में नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। यदि मतदाता यह मानने लगें कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है या चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, तो लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। इतिहास गवाह है कि अनेक देशों में चुनावी संस्थाओं पर अविश्वास ने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव और लोकतांत्रिक संकट को जन्म दिया है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में विश्वास बनाए रखना राष्ट्रीय आवश्यकता है।

समकालीन समय में सोशल मीडिया ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। किसी भी घटना के तुरंत बाद अपुष्ट सूचनाएं, अफवाहें और राजनीतिक दावे तेजी से फैलने लगते हैं। ईवीएम जलने जैसी घटनाएं सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के दावों और प्रतिदावों का विषय बन जाती हैं। ऐसे वातावरण में तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रशासन और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे त्वरित, सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता के सामने रखें। इस पूरे विवाद का एक व्यापक राजनीतिक आयाम भी है। लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य सरकार और संस्थाओं से प्रश्न पूछना है। यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखें। निराधार आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, जबकि प्रमाण आधारित आलोचना उन्हें अधिक उत्तरदायी और मजबूत बनाती है।

चुनावी संसाधनों के भंडारण और सुरक्षा के लिए और अधिक कठोर मानक विकसित किए जाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग, स्वतंत्र ऑडिट, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया को और अधिक व्यापक तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। साथ ही चुनाव आयोग को जनसंचार के माध्यमों का बेहतर उपयोग करते हुए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े भ्रमों और संदेहों का समय-समय पर समाधान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने की घटना केवल एक प्रशासनिक दुर्घटना नहीं है, यह लोकतंत्र के उस मूल प्रश्न को सामने लाती है कि नागरिकों का विश्वास कैसे सुरक्षित रखा जाए। लोकतंत्र केवल मतपेटियों या मशीनों से नहीं चलता, बल्कि उस भरोसे से चलता है जो नागरिक चुनावी प्रक्रिया पर करते हैं। ईवीएम की सुरक्षा, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और मीडिया की संवेदनशीलता, ये सभी मिलकर उस विश्वास की रक्षा करते हैं। यदि संदेह की लपटें लगातार फैलती रहीं और उनका समय पर समाधान नहीं हुआ, तो वे केवल मशीनों को नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी झुलसा सकती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हर प्रश्न का उत्तर तथ्यों से दिया जाए, हर आशंका का समाधान पारदर्शिता से किया जाए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी जनविश्वास को हर परिस्थिति में अक्षुण्ण रखा जाए।

युद्ध और अल नीनो के बीच खड़ी दुनिया

सामयिक

मनीषा मंजरी

लेखक साहित्यकार हैं।

सुबह की पहली किरण जब खिड़की पर दस्तक देती है, तो दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, कोई किसान अपनी खेत की मेड़ों पर मौसम का अनुमान लगा रहा होता है और कोई माँ अपने परिवार के लिए दिन की शुरुआत कर रही होती है। लेकिन उसी समय पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में सायरनों की आवाज़ गूँज रही होती है, बमों के धमाकों से घरों की दीवारें काँप रही होती हैं और भय से भरी आँखें यह पूछ रही होती हैं कि आखिर इंसान ने इतनी प्रगति करके भी शांति को क्यों नहीं चुना।

हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ, मानव सभ्यता अपनी उपलब्धियों के शिखर पर दिखाई देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लेकिन इसी समय दो ऐसी वास्तविकताएँ हमारे सामने खड़ी हैं जो हमारी संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और सामूहिक उत्तरदायित्व की परीक्षा ले रही हैं। युद्ध और जलवायु संकट।

हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता का कारण बना हुआ है। मध्य-पूर्व लंबे समय से संघर्षों का केंद्र रहा है, लेकिन जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाला राष्ट्र आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं, तो उसका प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। मिसाइलें केवल सैनिक ठिकानों को नहीं निशाना बनातीं; उनका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और करोड़ों आम लोगों के जीवन तक पहुँचता है।

युद्ध का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसका निर्णय अक्सर सत्ता के गलियारों में लिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं चाहा। एक सैनिक का परिवार, विस्थापित होते बच्चे, अपनी मिट्टी छोड़ने को मजबूर बुजुर्ग, टूटते घर और बिखरते सपने। युद्ध का वास्तविक चेहरा यही है। इतिहास हमें विजेताओं के नाम याद रखता है, लेकिन उन अनगिनत लोगों के आँसू दर्ज नहीं करता जो हर संघर्ष के बाद अपनी दुनिया फिर से बनाने की कोशिश करते हैं।लेकिन क्या केवल युद्ध ही हमारे समय का संकट है? शायद नहीं। इसी समय प्रकृति भी अपने बदलते स्वभाव से हमें लगातार चेतावनी दे रही है। अल नीनो, जो प्रशांत महासागर के तापमान में परिवर्तन से जुड़ी एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, दुनिया भर के मौसम चक्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। कमजोर मानसून, असामान्य वर्षा, लंबे सूखे, भीषण गर्मी और फसलों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव केवल मौसम की घटनाएँ नहीं हैं; वे करोड़ों लोगों की आजीविका, भोजन और भविष्य से जुड़े प्रश्न हैं।किसान जब आसमान की ओर देखता है तो वह केवल बारिश का इंतज़ार नहीं करता; वह अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और पूरे वर्ष की उम्मीदों को बादलों से जोड़ देता है। यदि वर्षा समय पर न हो, यदि धरती की नमी छिन जाए या यदि बाढ़ उसकी मेहनत को बहा ले जाए, तो उसका संकट किसी आँकड़े से कहीं अधिक गहरा होता है।

सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब युद्ध और जलवायु संकट एक-दूसरे के समानांतर चलने लगते हैं। यदि युद्धों के कारण तेल और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो और दूसरी ओर अल नीनो के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आए, तो महँगाई, खाद्य असुरक्षा और आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो स्पष्ट होता है कि सभ्यताओं का पतन केवल तलवारों से नहीं हुआ। सूखा, अकाल, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय परिवर्तन भी मानव समाजों को गहराई से प्रभावित करते रहे हैं। आज का समय हमें यह याद दिलाता है कि मानवता की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं। राजनीतिक सीमाएँ हमें बाँट सकती हैं, लेकिन जलवायु संकट किसी पासपोर्ट या वीज़ा को नहीं पहचानता।

विडंबना यह है कि हमने विज्ञान में जितनी प्रगति की है, उतनी प्रगति शायद करुणा में नहीं कर पाए हैं। हम ग्रहों की दूरी माप सकते हैं, लेकिन अपने ही समाज में बढ़ती असमानताओं और पीड़ाओं की गहराई को समझने में अक्सर असफल हो जाते हैं। हम भविष्य की तकनीकें गढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान की संवेदनहीनता से जूझ रहे हैं।

ऐसे समय में साहित्य, कला और विचार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें आँकड़ों के पीछे छिपे मनुष्यों को देखने की दृष्टि देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि समाचारों में दिखाई देने वाले चेहरों के भी सपने होते हैं, रिश्ते होते हैं और भय होते हैं। वे हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वह केवल आर्थिक वृद्धि है, या उसमें मानवीय गरिमा और पर्यावरणीय संतुलन भी शामिल हैं? फिर भी निराशा अंतिम सत्य नहीं है।

मानव इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उसी इतिहास में पुनर्निर्माण, सहयोग और आशा की अनगिनत कहानियाँ भी दर्ज हैं। युद्धों के बाद शहर फिर बसे हैं। अकालों के बाद खेतों ने फिर हरियाली ओढ़ी है। आपदाओं के बाद लोगों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवन को फिर से शुरू किया है। यही मनुष्य होने का सबसे सुंदर पक्ष है, टूटने के बाद भी निर्माण करने की क्षमता।

आज आवश्यकता केवल कूटनीतिक समझौतों और आर्थिक नीतियों की नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम यह स्वीकार करें कि पृथ्वी हमारी साझा विरासत है और मानवता हमारी साझा पहचान। यदि किसी देश का बच्चा युद्ध से भयभीत है या किसी किसान की फसल जलवायु संकट से नष्ट हो रही है, तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की असफलता है। युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि घृणा कितनी विनाशकारी हो सकती है, और अल नीनो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ असंतुलन की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा प्रश्न है-क्या हम अपनी बुद्धिमत्ता को करुणा के साथ जोड़ पाएँगे? क्या हम प्रगति को उत्तरदायित्व के साथ परिभाषित कर पाएँगे? क्योंकि अंततः आने वाली पीढ़ियाँ हमें हमारी सैन्य शक्ति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से याद रखेंगी कि जब पृथ्वी और मानवता दोनों संकट में थीं, तब हमने कौन-सा रास्ता चुना था? विनाश का या सहअस्तित्व का।

कौन किसके संपर्क में है?

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

वैसे तो हर किसी क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखती है कि कौन किसके संपर्क में है? क्योंकि ऐसा कहा और माना जाता है कि आदमी जब किसी के साथ संगत करता है तो उसका रंग उस पर चढ़े बिना नहीं रहता। अब यदि जिंदगी में कोई सुनहरा अवसर मिल जाने का योग बन जाएं, तो कोई-कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपनी निष्ठा और समर्पण भाव को विशुद्ध रूप से अक्षुण्ण रख पाते हैं। अन्यथा सुना है कि आजकल हर ईमान की कीमत हुआ करती है लेकिन जो ईमान किसी कीमत पर नहीं बिकता, बहुत संभव है कि उसकी पर्याप्त कीमत नहीं लग पाई हो। जिसके चलते ईमान का ईमान बना हुआ है।

हालांकि मैं समझता हूं कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर भी जमाने के दस्तूर को देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने गलत नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत कुछ संभावना इस बात की होती है कि आदमी की जिंदगी में कभी-कभी कमजोर पल भी आ जाते हैं। जिसके चलते आदमी अपने निष्ठा और समर्पण भाव को ताक पर रख दिया करता है। वैसे भी सियासत में रहकर जमाने भर की उठापटक और भागदौड़ करते हुए अंतर्मन के कोने-कोने में यह भाव विद्यमान होता ही है कि ऐसे-वैसे या चाहे जैसे-तैसे बस एक बार सत्ता की चाबी हाथ लग जाएं।

हालांकि इस भाव को कोई जाहिर नहीं करता लेकिन सियासत में आदमी का हाव-भाव और व्यवहार चींख-चींख कर इसी तथ्य की गवाही देता है कि वादे चाहे जो किए जाएं, नारे चाहे जो लगाए जाएं, लेकिन आजकल के दौर में राजनीति भी निवेश करने का और तगड़ा लाभ प्राप्त करने का एक आसान सा जरिया हो गई है। बस जरूरत इस बात की हुआ करती है कि आप सामने आए अवसर को पहचाने। वैसे भी जिंदगी में सुनहरे अवसर बार-बार नहीं मिला करते। दरअसल जन्म-जन्मांतर के शुभ कर्म उदय में आने पर ही ऐसी कोई संभावना बनती है कि हमारे अपने मत की कीमत हमारी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकती हो।

यह तथ्य जग जाहिर है कि जब दो खरबूजे आमने-सामने हो तो खरबूजे का खरबूजे को देखकर रंग बदलना बहुत हद तक स्वाभाविक हो जाता है। आजकल संपर्क के लिए संचार माध्यम इतने विकसित हो चुके हैं कि आदमी चाहे तो मजे से निहायत ही एकांत के पलों में भी दीन दुनिया की खबर रखते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठी शख्सियत से अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। दरअसल संपर्क तो निजी पसंद के आधार पर तय होता है लेकिन कभी-कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि किसी एक का दूजे से संपर्क करना उसके अपने व्यापक हित में समय की मांग बन जाता है। एक प्रकार से इसे 'धंधे के सीजन' के रूप में भी देखा जा सकता है।

वैसे ऐसे अवसर हर किसी के लिए कोई बार-बार नहीं आते। यही कारण है कि आमतौर पर गर्म लोहे पर चोट कर दी जाती है और सामने वाले की हैसियत और महत्व को अपने खाते में जमा कर लिया जाता है। अब यह जो धंधे का सीजन है, इसका लाभ लेने वाले तात्कालिक रूप से तो लाभान्वित होते ही हैं लेकिन उन्हें इसका दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होने की भी प्रबल संभावनाएं रहा करती है। सियासी जगत में कभी-कभी यह प्रश्न काफी अहम हो जाता है कि कब, कौन, कहां और किससे संपर्क स्थापित कर सकता है। ऐसे में अपने कुनबे की साख बचाने और कायम रखने के लिए सियासत की शतरंजी बाजी के प्यादों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखना आवश्यक हो जाता है।

ऐसी स्थिति में उनके लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश रहा करती है। आमतौर पर यह वह स्थान होता है जहां संबंधित दल की हुकूमत चलती हो। इसके लिए अपनी हुकूमत वाले राज्य में सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट से भला और कौन सा अच्छा स्थान हो सकता है। वैसे अपने खेमे के समूह को ठहरने को तो होटल में भी ठहराया सकता है लेकिन ऐसा करने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि निहायत ही एकांत के पलों मे कब, कोई किससे संपर्क कर लेवे। बड़ी अजीब बात है कि सियासत में कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है जब अपने ही बंदों को एक प्रकार से बंधक बनाया जा सकता हो।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बचपन से प्रतिभाशाली जिज्जी की महानता का सफ़र

व्यंग्य

रिंकल शर्मा

लेखक साहित्यकार हैं।

दुर्भाग्य से, जिज्जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थीं। इसकी जानकारी उनके अलावा किसी और को नहीं थी। वे घर की मँझली औलाद थीं, इसलिए माता-पिता ने अतिरिक्त लाड़-प्यार देकर उन्हें बिगाड़ने की भूल नहीं की। जिज्जी शुरू से ही बेहद शांतिप्रिय थीं, उनकी कभी किसी से कहासुनी नहीं हुई, क्योंकि वे सीधे हाथापाई में विश्वास रखती थीं, इससे मामला जल्दी निपट जाता था।

बचपन से ही जिज्जी बड़े ऊँचे ख्यालात की थीं। ये डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने का ख्याल उन्होंने कभी नई पाला क्योंकि ये सब तो आम लोग करते हैं, उनका सोचना था कि जब भगवान ने उन्हें औसत से थोड़ा नीचे रखा है, तो ज़रूर उनका जन्म कुछ असाधारण करने के लिए हुआ है। हाँ, उनके घरवाले उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि जिज्जी 'कुछ' नहीं करेंगी। जिज्जी को लगता था कि वो 'कुछ बड़ा' करेंगी। आखिरकार थोड़े बहुत सोच-विचार के बाद उन्होने कवयित्री बनने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे उनके ठोस, तर्कसंगत और पूरी तरह स्वार्थ-रहित कुछ ख़ास कारण थे। पहला - अँग्रेजी में उनका हाथ तंग था। अंग्रेज़ी में जिज्जी उतनी ही निपुण थीं जितना आम आदमी सरकारी नीतियों को समझने में। सौभाग्य से हिन्दी साहित्य इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ अंग्रेज़ी को कोसना स्वीकार्य भी है और अनिवार्य भी। दूसरा साहित्य में रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं होती। जीवनभर आपकी कवितायें भले अधपकी रह जाएँ लेकिन बाल पकते-पकते आपको अध्यक्ष पद पर प्रमोशन मिल ही जाता है। तीसरा- ग्लेमर के मामले में साहित्य मरुस्थल जैसा है, जहां मृगतृष्णा भी ठंडक देती है। कवयित्री के पास कवित्त ज्ञान ज्यादा न हो पर सौंदर्य और आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, जोकि उनके पास थोक में था।

आखिरी सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें जीवन में सीधे 'महान' बनना था वो भी बिना मेहनत, शॉर्टकट से। और साहित्य की दुनिया ऐसी है जहां शुरुआत में भले ही लोग आपको हल्के में लें, लेकिन समय के साथ वही लोग आपको 'वरिष्ठ', 'प्रख्यात' और 'महान' जैसे शब्दों से अलंकृत कर देते हैं।

हमारी जिज्जी के लिए कला का अर्थ निकला- कल-आ, कल-आ। क्योंकि जब भी जिज्जी किसी भोले-भाले श्रोता को पकड़कर, उसे अपनी कविता सुनाने की कोशिश करतीं, उसके चेहरे पर अचानक राष्ट्रीय संकट उमड़ आता। वह कभी घड़ी देखता, कभी मोबाइल टटोलता, अपनी इतनी व्यस्तता दिखाता जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसी के भरोसे चल रही हो। फिर बनावटी, शिष्ट मुस्कान से कह देता-'वाह! बहुत बढ़िया, कल आना, आराम से सुनूंगा।' लोगों ने उन्हें सुनने के बजाय टालना शुरू किया पर जिज्जी ने इसे प्रोत्साहन समझकर, कवि-सम्मेलनों की ओर रुख किया। बस यहीं से उनका असली साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ। लेकिन इस सफ़र में जिज्जी के सामने नई समस्या थी कि मंचों के लायक 'ठोस' कविता लिखी कैसे जाए? उन्होने थोड़ा सोचा, फिर तुरंत सोचना बंद कर दिया क्योंकि सोचने में मेहनत लगती है। फिर समस्या का सरल समाधान निकाला कि- खुद क्यों लिखें? जब दुनिया में पहले से इतनी कविताएँ मौजूद हैं, तो नई लिखकर साहित्य पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जाए? फिर साहित्य में तो वैसे भी ईमानदारी दुर्लभ है। इसीलिए उन्होंने 'सृजनात्मक उधारवाद' को अपनाया। कवि सम्मेलनों पर अध्ययन के बाद उन्हें यह पता चल चुका था कि आधे से ज़्यादा कवि-कवयित्रियाँ इसी बिरादरी के हैं। यह एक ऐसा विस्तृत परिवार है, जहाँ लोग, एक-दूसरे की रचनाओं से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना बना लेते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आम भाषा में जिसे 'चोरी' कहते हैं, परिवार के लोग इसे 'प्रेरणा' कहते हैं। मगर जिज्जी ने इसे 'साहित्यिक रिसाइकलिंग' का नाम दिया। वर्तमान में तो पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइकलिंग बहुत आवश्यक है फिर चाहे कचरा हो या कविता।

साहित्यिक रिसाइकलिंग की कला सीखने में बारीकियों पर उन्होने ख़ास ध्यान दिया जैसे- किस रस की, कौन सी कविता, कहाँ से उठानी है, कितने शब्द बदलने हैं, कहाँ अल्पविराम लगाना है और कहाँ भावनात्मक विराम देना है इत्यादि। धीरे-धीरे उन्होने मंचों पर धावा बोलना शुरू किया और चिल्ला-चिल्लाकर ओज की कवितायें पढ़नी शुरू कर दीं। समय के साथ उन्होने मंचीय रणनीति भी सीख ली। जिज्जी मंच पर पहुँचते ही आयोजक की खूब प्रशंसा करतीं ताकि अगली बार का बुलावा पक्का हो जाए। फिर, मंच पर विराजमान अध्यक्ष को गुरु बताकर, अपनी कविता को उसके गले की हड्डी बना देतीं। अब, अध्यक्ष के पास उनकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। जब अध्यक्ष तारीफ़ों का फ्लाईओवर बना दे, तो आलोचक और समीक्षक वैसे ही चुप हो जाते हैं जैसे मीटिंग में बॉस के बोलने के बाद, कर्मचारी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बतौर कवयित्री जिज्जी पारंगत हो चुकी हैं। और अब उन्होने साहित्य की दूसरी विधाओं में भी दखल देना शुरू कर दिया है ताकि कोई भी मंच उनसे अछूता न रहे। साथ ही बड़े-बड़े पुरस्कार देने वाले संस्थानों में घुसपैठ भी शुरू कर दी है। वह दिन दूर नहीं जब जिज्जी की कविताएँ पाठ्यक्रम में लगाई जाएँगी, उन पर शोध होंगे, स्कूलों में उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी 'साहित्यिक रिसाइकलिंग' की परंपरा को आगे बढ़ा सकें। और सदियों तक जिज्जी 'महान साहित्यकार' के रूप में जानी जाएँगी।

मुद्दा

डॉ. अंशुल उपाध्याय

यूजीसी की सीनियर रिसर्च फैलो

घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता की आवश्यकता

सर्वेक्षण में पाया गया है कि 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28 प्रतिशत) है, जिसके बाद महिलाओं के साथ भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा हुई है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में अपराधी पति होता है। जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें शारीरिक, यौन, या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा करने की संभावना आधी (21 प्रतिशत) होती है। जबकि स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले 43 प्रतिशत लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज़्यादा होता है।

भारत में घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। वे महिलाएं जो नौकरी पेशा नही है और घर पर रहकर ही अपने बच्चो और परिवार के पोषण के लिये अपना सारा समय लगा देती है। उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पति के द्वारा कुछ धनराशि प्रति माह प्राप्त होनी ही चाहिए। इससे न केवल महिलाओं को सबलता मिलेगी बल्कि घरेलू हिंसा के मामलो में भी कमी आएगी। भारत मे लगभग घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005 घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा। क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना; या पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुँचाना।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28 प्रतिशत) है, जिसके बाद महिलाओं के साथ भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा हुई है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में अपराधी पति होता है। जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें शारीरिक, यौन, या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा करने की संभावना आधी (21 प्रतिशत) होती है। जबकि स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले 43 प्रतिशत लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज़्यादा होता है।

एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक, भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 31प्रतिशत (एनएफएचएस - 4), से 32 प्रतिशत के बीच हैं। 2019-2021 नई एनएफएचएस - 5 रिपोर्ट 12 मई 2022 के अनुसार भारत मे 92 प्रतिशत महिलाये बिना मेहनताना लिये घरेलू काम करती हैं जबकि सिर्फ 27 प्रतिशत पुरूष ही ऐसा करते है।

भारतीय महिलाओं को जो नौकरी पेशा नही है। अपने पति द्वारा प्रति माह कुछ धनराशि अवश्य दी जानी चाहिए, इससे ना केवल घरेलू हिंसा के मामलों में बल्कि महिलाओ के मानसिक तनावो में भी कमी आयेगी। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी है मगर नौकरी पेशा नही है उन्हें हर वक्त ये बात कचोड़ती तो अवश्य होगी की काश वो भी औरो की तरह अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही सही कुछ रुपए कमा सकती।

चूंकि शिक्षा का व्यक्ति के मानसिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मानसिक विकास हो जाने के बाद व्यक्ति अपना अच्छा बुरा स्वयम समझ पाता है। ऐसे मे किसी मानसिक रूप से विकसित महिला का घर पर रहना कई बार उसकी मजबूरी होती हैं। कई बार बच्चों के पालन हेतु तो कई बार ससुराल वालों की सहमति से। और मन में चल रहे द्वंद्व का सामना जब महिलाएं नही कर पाती तो डिप्रेशन, हाई बीपी,मधुमेह जैसे रोगों का शिकार हो जाती हैं। इसलिए अगर महिलाओं को सबल बनाना है तो जरूरी नही परिवार के दायित्व के साथ उन्हे नौकरी पेशा होने को मजबूर किया जाये। इस समस्या का समाधान है,घरेलू महिलाओ को प्रति माह उनके पति द्वारा कुछ धनराशि प्रदान किया जाना।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में, जब हम भारत की महिलाओं को देखते हैं तब उनमें सशक्तिकरण केवल स्वयं रोजगार से जुड़ने पर नहीं आता अपितु उनके पास अगर कुछ मात्रा में धन रहे तो खुद व खुद उस धन को किस तरह से अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं में खर्च करना है यह समझ महिलाओं में आ जाती है। भारत में अधिकांश जगहों पर महिलाएं ग्रहणी है और अपना घर संभालती हैं। पर यह हमारी विडंबना है कि हमने अपने घर की महिलाओं को वित्त का अधिकार नहीं दिया ना ही वित्त संबंधी मामलों में हम घर की महिलाओं की सलाह लेते हैं। जबकि हमारे वित्तमंत्री जी की स्वयं एक महिला है जो भारत का बजट बनती हैं। और दूसरी तरफ एक वह महिला है जो अपना घर चला रही हैं तो क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं होगी कि वह घर के बजट को सही तरीके से चला सके अत: हम बेटियों को तो आगे से पढ़ाते हैं सब उन्हें सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं पर फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं की हमारी बेटी ही तो कल किसी और के घर की बहु बनेगी। अत: अपनी बेटी को हमेशा धन देते रहना और बहू को उससे वंचित रखना क्या ये सही है? इसलिए भारत में यह प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए की विवाह के पश्चात यदि कोई महिला नौकरी पेशा नही है तो उसे उसक उसके पति के द्वारा मासिक तौर पर कुछ धनराशि अवश्य प्रदान की जाए। इससे न केवल घरेलू महिलाएं अपनी जरूरत की चीजें खुद ले पाएंगी साथ ही घर की छोटी-छोटी चीजों के लिये उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना होगा। जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ पारिवारिक शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

ऐतिहासिक फैसला

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

गृहिणियाँ हैं राष्ट्र निर्माता

सर्वोच्च न्यायालय का उक्त फैसला हरियाणा में 2001 में एक हादसे में महिला की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। महिला के पति और तीन बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से मुआवजा मांगा था। अधिकरण ने 2003 में 2 लाख 42 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया था। इस फैसले से नाखुश परिवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2024 में जारी फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार कर दिया। साथ ही 7.5 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया था। इस फैसले से भी असंतुष्ट दावेदार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिला की मृत्यु घरेलु देखभाल का नुकसान है। मुआवजे की गणना के लिए महिला के घरेलु श्रम का मूल्य कम से कम 30 हजार रूपए प्रतिमाह माना जाए। यह राशि हर तीसरे साल 10 प्रतिशत बढ़ेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस श्री संजय करोल और कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 25 साल पहले एक हादसे में अपनी पत्नी को खो चुके व्यक्ति के लिए 62 लाख 77 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अन्य मामलों में भी उदाहरण बनेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में वाहन दुर्घटना पर महिला की मौत पर मुआवजे से जुड़े सभी मामलों में घरेलु देखभाल के नुकसान का अलग मद जुड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि अब तक गृहिणियों की मौत पर मुआवजा तय करते समय उनकी आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानी जाती थी। उन्हें कुशल या अकुशल मजदूर की श्रेणी में रखा जाता था। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये महिला के योगदान का गंभीर अवमूल्यन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गृहिणी परिवार के कमाऊ सदस्य पर निर्भर मानी जाती है, जबकि असल में घर की व्यवस्था काफी हद तक उस महिला पर ही निर्भर होती है। कोर्ट ने लैंगिक भूमिकाओं पर यह भी कहा कि शादी का मतलब नौकरानी रखना नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का उक्त फैसला हरियाणा में 2001 में एक हादसे में महिला की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। महिला के पति और तीन बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से मुआवजा मांगा था। अधिकरण ने 2003 में 2 लाख 42 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया था। इस फैसले से नाखुश परिवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2024 में जारी फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार कर दिया। साथ ही 7.5 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया था। इस फैसले से भी असंतुष्ट दावेदार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े सभी प्रकरण एक साल में निपटाएं जाने चाहिए और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इसकी निगरानी करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 साल से अधिक समय से लंबित मामले पहले निपटाएं जाने चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का उक्त आदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। इसका सही मायने में क्रियान्वयन देशभर में चल रहे मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े सभी प्रकरणों में किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार गृहिणी को मात्र होममेकर नहीं मानते हुए राष्ट्र निर्माता बताया है। यह फैसला भविष्य में सभी पर लागू होगा। यह भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब देश के सभी उच्च न्यायालयों को और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को अपने फैसले लेते समय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त ऐतिहासिक फैसले को नजीर मानते हुए अपने फैसले देना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्थक सिद्ध होगा।

श्रद्धा की चोरी-करूणता कहां लुप्त हो गई?

विचार

बंसीलाल परमार

लेखक शिक्षक हैं।

मेरे संदर्भ में एक खबर है। इस खबर का शीर्षक है, दीयों से तेल इकट्ठा कर रही बच्ची की वायरल तस्वीर के पीछे का सच ये है मुफलिसी की कहानी। यह तस्वीर 31 अक्टूबर 2019 की। दूसरी अखबार कतरन वर्तमान जून 2026 की है। इसका शीर्षक है, श्रीराम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले दो दबोचे गए। यह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों से चढ़ावे की धनराशि की चोरी का मामले से जुड़ी खबर है। दोनों खबरों के बीच सात वर्ष का फासला है।

2019 की तस्वीर जिसमें अयोध्या में दीये जलाने के कीर्तिमान के दूसरे दिन की है, जहां एक गरीब लड़की दीयो के बचे तेल को बोतल में इकट्ठा कर रही थी। कार्बोहाइड्रेट से देह चलाने वालों की इच्छा कभी-कभी वसा पाने की भी हो जाती है किंतु उनकी आय इतनी नहीं होती कि वे शरीर के लिए जरूरी फेस यानी वसा भी जुटा पाए। ऐसे में जब सामने तेल का सैलाब हो तो बच्ची जरूरत का तेल इकट्ठा करेगी ही। दीयों की ज्योति में प्रयुक्त हुआ तेल हमारी आध्यात्मिकता को प्रकाशित कर रहा है। क्या लोगों को वंचित रख कर नदी के घाट को यूं रोशन करना क्या गर्व करने योग्य है?

यह श्रद्धा की चोरी का मामला है जहां भोजन में चिकनाई के लालच से श्रद्धापूर्वक जलाए गए दीपकों का तेल ले जाया जा रहा है। इस घटना के बाद के वर्षों में दीपदान वाली जगह पर पुलिस लगा दी गई ताकि इस तरह सेंध लगाकर तेल न चुराया जा सके।

दूसरा चित्र हमारे मंदिरों में दान रुप में परिणित होकर दानपेटी तक पहुंचने वाली श्रद्धा निधि का व्यक्तिगत उपयोग का है। मंदिर में मिले दान की राशि का उपयोग कर खुद का महल खड़ा कर लें तो इसे चोरी माना जाए या नहीं?

मैं स्वयं अपने कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा क्योंकि इन बिंदुओं पर विचार करना अधर्मी या देशद्रोही कहलाने का आमंत्रण होता है। यह बहाव के विरुद्ध भी जाता है। मैंने रामचरित मानस, कवितावली, दोहावली, विनय-पत्रिका पढ़ी है। वे उनके छंद आज भी मुंह जबानी याद है।

ऐसो कौन उदार जग माहीं
बिन सेवा जो द्रवे दीन पर
राम सरिस कोऊ नाही।।

अर्थात् इस संसार में प्रभु श्री राम के समान उदार (कृपालु) और कोई दूसरा नहीं है, जो बिना किसी सेवा या प्रयास के ही दीन-दुखियों (गरीबों और असहायों) पर दया कर दे।

जाके प्रिय न राम विदेही
तजिये ताही कोटी बैरी सम
जदपि परम सनेही।

तुलसीदास जी यहां कहते हैं,जिन लोगों को भगवान राम और सीता (वैदेही) प्रिय नहीं हैं, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, भले ही वे आपके कितने ही परम स्नेही क्यों न हों।

अपने विचारों के कारण आज मैं स्वजनों, परिजनों व मित्रजनों से तजा गया हूं। ठीक, उसी तरह जैसे लंका में विभीषण का बहिष्कृत किया गया था। मैंने उत्तर रामचरित पढ़ा है। उसमें लिखा है, एको रस करुण एव। यानी सभी रसों या भावों का स्रोत करूण रस है। इन खबरों को देखते हुए मैं आज उस करुणा को खोज रहा हूं जो कभी सनातन धर्म का मूल आधार रहा है। अगर आपको यह करूण रस कहीं मिल जाए तो बताइगा।

शिक्षा प्रणाली

दुर्गेश्वर राय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संयोजक हैं।

शिक्षा सुधार सरकारी नीति न होकर एक साझा राष्ट्रीय मिशन बने

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली आज लगभग चौदह लाख से अधिक स्कूलों, चौबीस करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है। पिछले एक दशक में स्कूलों में बुनियादी ढाँचे जैसे बिजली, शौचालय और पेयजल की पहुँच के मामले में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है। इसी अवधि में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था का भी विस्तार हुआ है और कंप्यूटर, इंटरनेट तथा स्मार्ट कक्षाओं तक बच्चों की पहुँच बेहतर हुई है। इसके साथ ही, सामाजिक समावेशन के स्तर पर लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्रों के नामांकन में उत्साहजनक सुधार दर्ज किया गया है। महामारी के बाद के दौर में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार के संकेत भी मिले हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों का लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है।

जब देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शिक्षा की कसौटी केवल अक्षरों की सामान्य पहचान या कक्षाओं में भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं रह सकती। आधुनिक युग में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का सर्वांगीण संवर्धन करना है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई व्यापक नीति रिपोर्ट, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा, इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण को एक व्यवस्थित और व्यावहारिक धरातल प्रदान करती है। यह दस्तावेज़ वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक के एक दशक लंबे आंकड़ों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए भारतीय स्कूली शिक्षा के क्रमिक विकास, वर्तमान संरचनात्मक चुनौतियों और भविष्य के नीतिगत रोडमैप को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने एक न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वर्ष 1952 के मुदालियर आयोग और 1964 के कोठारी आयोग की अनुशंसाओं ने आधुनिक शिक्षा के बुनियादी ढाँचे की मजबूत नींव रखी थी। इसके बाद 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने देश भर में शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर विशेष बल दिया। वर्ष 1995 में शुरू की गई मिड-डे मील योजना ने स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उनके पोषण स्तर को सुधारने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे युगांतकारी कदमों से और अधिक सुदृढ़ किया गया। इसी ऐतिहासिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नए शैक्षणिक ढाँचे को प्रतिपादित किया। नीति आयोग ने पिछले एक दशक की इसी यात्रा का मूल्यांकन करने के लिए यूडायस प्लस 2024-25 के स्कूल से सम्बंधित आंकड़े, परख 2024 के परीक्षा स्तर, एनएएस के 2017 और 2021 के बच्चों के स्कोर और एएसईआर 2024 के बच्चों के पढ़ने की क्षमता आधारित आंकड़ों का उपयोग किया है।

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली आज लगभग चौदह लाख से अधिक स्कूलों, चौबीस करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है। पिछले एक दशक में स्कूलों में बुनियादी ढाँचे जैसे बिजली, शौचालय और पेयजल की पहुँच के मामले में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है। इसी अवधि में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था का भी विस्तार हुआ है और कंप्यूटर, इंटरनेट तथा स्मार्ट कक्षाओं तक बच्चों की पहुँच बेहतर हुई है। इसके साथ ही, सामाजिक समावेशन के स्तर पर लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्रों के नामांकन में उत्साहजनक सुधार दर्ज किया गया है। महामारी के बाद के दौर में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार के संकेत भी मिले हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों का लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है।

इन तमाम सकारात्मक बदलावों के बावजूद, इस तंत्र का सबसे बड़ा ढाँचागत संकट इसका पिरामिडनुमा स्वरूप है, जो उच्च स्तर पर जाते ही संकुचित हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है और वहाँ नामांकन दर भी काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जैसे-जैसे छात्र उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं, सकल नामांकन अनुपात तेजी से कम होता जाता है। यह डेटा साफ तौर पर दर्शाता है कि उच्च कक्षाओं तक पहुँचते-पहुँचते बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। देश में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो प्राथमिक से लेकर बारहवीं कक्षा तक की निरंतर शिक्षा एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं। यह संस्थागत विखंडन छात्रों को बार-बार स्कूल बदलने के लिए मजबूर करता है, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, देश में बड़ी संख्या में एकल-शिक्षक स्कूल और शून्य नामांकन वाले स्कूल भी मौजूद हैं, जो प्रशासनिक और वित्तीय अक्षमता को उजागर करते हैं।

नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद शिक्षा प्रणाली की कई प्रमुख प्रणालीगत और शैक्षणिक चुनौतियों की पहचान की है। कक्षाओं में आज भी वास्तविक वैचारिक समझ विकसित करने के बजाय केवल पाठ्यक्रम पूरा करने और रटने की पद्धति पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जिससे बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर में अंतर आ जाता है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी और उनकी असमान तैनाती एक अन्य बड़ी बाधा है। इसके अलावा, गैर-शैक्षणिक कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण शिक्षकों का वास्तविक शिक्षण समय भी काफी प्रभावित होता है।

सरकारी स्कूलों के प्रति समाज की बदलती धारणा के कारण निजी स्कूलों पर निर्भरता बढ़ी है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। साथ ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की गति अब भी धीमी बनी हुई है।

इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में एक विस्तृत नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कई प्रणालीगत और शैक्षणिक अनुशंसाओं को शामिल किया गया है। विद्यालय संरचना को सुधारने के लिए कम नामांकन वाले स्कूलों का साक्ष्य-आधारित युक्तिकरण करने और संसाधनों को साझा करने के लिए स्कूल परिसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

शासन सुधारों के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर खाली पड़े प्रशासनिक पदों को भरकर निरीक्षण व्यवस्था को अकादमिक परामर्श में बदला जाना चाहिए। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से एक समग्र समाज दृष्टिकोण विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें स्थानीय स्कूल प्रबंधन समितियों को भी मजबूत किया जाएगा।

शैक्षणिक स्तर पर अमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए क्षमता-आधारित मूल्यांकन को संस्थागत रूप देना आवश्यक है ताकि रटकर परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। प्रारंभिक शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, व्यक्तिगत शिक्षण और डेटा-संचालित प्रशासनिक निगरानी के लिए आधुनिक युग के डिजिटल प्लेटफॉर्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

भारत ने शिक्षा तक पहुँच और भौतिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण का पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब हमारे सुधारों का दूसरा चरण पूरी तरह से सीखने की गुणवत्ता और ढाँचागत निरंतरता पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए यह रूपांतरण केवल एक सरकारी नीति न होकर एक साझा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए।

पिपरिया-नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर मढ़ई एवं अविनाश ढाबा के अतिक्रमण को पुलिस एवं राजस्व टीम ने हटाया

सोहागपुर । पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग 22 पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई की तरफ जाने के रास्ते से पहले ग्राम पंचायत बंमोरीखुर्द मुख्य सड़क पर स्थित मढ़ई ढाबा एवं अविनाश ढाबा के मालिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के अतिक्रमण को हटाया । इस दौरान नवनियुक्त नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के साथ अतिक्रमण स्थल पर मौजूद थे। वहीं राजस्व टीम में नायब तहसीलदार रणजीत सिंह चौहान, पटवारी श्रीमति हिना खान, शैलेन्द्र ओनकर, स्वप्निल सोलंकी, राहुल पटैल,ग्राम कोटवार बम्होरीखुर्द, बारंगी, चीचली, बासखापा के अलावा जेसीबी मशीन भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम में शामिल थे। इसी अवसर पर तहसीलदार आर एस झरबड़े भी वहां पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि शहर एवं आसपास ऐसे स्थान चिन्हित किये जा रहे हैं। जहां शासकीय भूमि अथवा अन्य तरह के अतिक्रमण है। उन पर भी विधिनुसार कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक श्री साईं कृष्ण एस थोटा की अनूठी पहल से पुलिसकर्मियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। उक्त अनूठी श्री साईं कृष्ण एस थोटा ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के जन्म दिवस पर मंगलमय शुभकामनाओं का संदेश प्रेषित कर रहे हैं। ऐसा ही वाकिया आज सोहागपुर में घटित हुआ ।जिसमें एएसआई गणेश राय का जन्मदिवस था। आपने उनको बधाई एवं शुभकामनाओं का संदेश पत्र भेजा। उक्त संदेश पत्र नवनियुक्त नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी ने एएसआई गणेश राय को प्रदान किया। इससे पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों में प्रसन्नता है। वहीं यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह संदेश पुलिसकर्मियों के लिए आत्मबल बढ़ाने का संबल है।

वाहन चालक नहीं करते यातायात नियमों का पालन, इसलिए बढ़ रहे सड़क हादसे

● 5 माह में 467 सड़क हादसे, 194 की मौत

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले में वाहन चालकों के लिए सडक़ सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हेलमेट की अनदेखी, नियमों को ताक पर रखना और तेज गति से वाहन चलाने के कारण सड़क हादसों में तेजी से इज़ाफा हो रहा है। अभी 5 माह यानि जनवरी से मई तक 467 सड़क़ हादसे हो चुके है। जिसमें 194 लोगों की जान चली गई, वहीं 502 घायल हुए है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण युवा बाइक सवारों के हेलमेट का उपयोग नहीं करने और लापरवाह तरीके से तेज रफ्तार बाइक दौड़ाने की आदतें, सडक दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही हैं। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस और ट्रॉफिक पुलिस सडक़ पर उतरकर लोगों को जागरूक भी करती है, मगर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। कुछ वर्षों की बात की जाए को सबसे अधिक दुर्घटनाएं बाइक सवारों के कारण हुईं, जो तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए या अपनी जान गंवा बैठे। यातायात पुलिस का साफ कहना है, कि हेलमेट सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर बाइक सवारों के लिए। सडक़ दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जानलेवा चोटें सिर पर ही आती हैं। सिर पर गंभीर चोट लगने से दुर्घटना में मृत्यु का खतरा 60 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया गया है, लेकिन शहर में हेलमेट पहनने की आदत बहुत कम है, जिससे हर वर्ष कई जानें चली जाती हैं। हेलमेट न पहनने के कारण हर वर्ष मृत्युदर और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हेलमेट का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह सिर की सुरक्षा करता है और दुर्घटना के दौरान होने वाली चोटों को काफी हद तक कम करता है।

जिले में सड़क़ हादसों की तीन बड़ी वजह - जिले में सडक़ हादसों के पीछे तीन वजहों को मुख्य कारण माना जा रहा है। जिन्हें सुधारने की जरूरत है। पहली वजह यह कि बैतूल-खंडवा मार्ग का महुपानी मोड़, बरेठा घाट और तासी घाट जैसे इलाके ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं। यहां साइन बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स नहीं हैं। दूसरी वजह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, पिकअप, ट्रकों जैसे मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना भी हादसों का कारण बन रहा है। वहीं तीसरी वजह जिले में ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय लापरवाही बरतना खास वजह है। लोग वाहनों की गति निर्धारित से अधिक रखते है। जिससे वजह स्वयं हादसों का शिकार होते है, साथ ही दूसरों को भी गंभीर रूप से चोटिल करते है। कई बार हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है।

हेलमेट जरूरी, फिर भी इसे करते है नजरअंदाज- बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन गंभीर है। आये दिन अभियान चलाकर ट्रॉफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाही करती है, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा। बैतूल जिले की सडकों पर चालक बिना हेलमेट पहने धड़ल्ले से दो पहिया वाहन दौड़ाते हैं। पुलिस से बचने के लिए कई वाहन चालक हेलमेट साथ लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन सिर पर नहीं पहनते। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर दुपहिया वाहन चालकों के लिए जब हेलमेट लगाना अनिवार्य है, फिर क्यों लोग अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहे। पुलिस जब चेकिंग अभियान चलाती है तब लोग या तो जुर्माना भरते है या फिर पैरवी के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते।

जागरूकता की कमी या फिर जिंदगी से प्यार नहीं - यातायात पुलिस के द्वारा वसूले गये जुर्माने की राशि बताती है कि किस तरह से लोग हेलमेट को नजरअंदाज कर रहे हैं और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अर्थदंड होने के बाद भी लोग हेलमेट लगाना क्यों पसंद नहीं करते है। क्या जागरूकता की अभी भी लोगों में कमी है या फिर उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जब लोग गाड़ी खरीदते है, तब भी हेलमेट अनिवार्य रूप से दिया जाता है, लेकिन हेलमेट को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है।

8 प्रतिशत लोग भी नहीं लगाते हेलमेट - जिले और शहर में कुछ सालों में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। सडकों पर ट्रॉफिक का दबाव बढ़ा है। सडक़ हादसों में इजाफा हुआ है। इन सडक़ हादसों को कम करने के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन शहर में 8 फीसदी भी वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते है, जबकि दो पहिया वाहन चलाते समय हुए हादसों में सर्वाधिक मौत बिना हेलमेट वालों की हुई है। कुछ समय पहले तो यह भी कहा गया था कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के आने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाए, लेकिन यह तमाम नियम, कानून हवा हवाई हो गए। जागरूक लोगों का कहना है कि वाहन चालक हेलमेट तो लेते हैं, लेकिन उसे लगाते नहीं है। घर में रख लेते हैं। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने से वह भी सुरक्षित नहीं रहते और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालते है।

सड़क हादसे रोकने के लिये पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा किये गये उपाय...

(1) शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
(2) सोशल मीडिया, फ्लेक्स बैनर एंव पेम्पलेट वितरण कर यातायात नियमों की जानकारी।
(3) सडक सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क डिजाइन, रोड मार्किगं, रोड शाइनेज लगाना।
(4) एक्सीडेंट जोन एरिया को चिन्हित कर सडक निर्माण एजेंसी से शॉर्ट टर्म परिशोधन कार्य कराना।
(5) व्यवसायिक वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाना और नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाही।
(6) नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर स्थित जंक्शन पाईंट पर एप्रोच रोड से आने वाले वाहनो को रोककर दाहिने-बाये देखकर मार्ग कास करने की समझाइश।

इनका कहना है - सडक हादसों को कम करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर और पेम्पलेट, बैनर, पोस्टर सहित अन्य माध्यमों से वाहन चालकों को जागरूक करते है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाही भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी वाहन चलाते समय लोग नियमों की अनदेखी और लापरवाही करते है। जिससे सडक हादसे होते है।

- गजेन्द्र कैन, प्रभारी, यातायात पुलिस, बैतूल

केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम रिंगढाना में आगजनी प्रभावित परिवारों से भेंट कर हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

बैतूल। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने 15 जून को भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिंगढाना का दौरा कर हाल ही में हुई आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुन उन्हें ढांढस बंधाया तथा आवश्यक राहत सामग्री प्रदान कर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि ग्राम रिंगढाना में हुई आगजनी की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। किसी भी परिवार के लिए अपना घर, जीवनभर की मेहनत से अर्जित सामग्री और अपनी स्मृतियों को एक ही पल में नष्ट होते देखना अत्यंत पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कठिन समय में उनके साथ खड़े होकर उन्हें संबल अवश्य प्रदान किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार जनहित और सेवा के भाव से कार्य कर रही है तथा संकट की इस घड़ी में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तत्परता बरतने तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की किसी भी स्थिति में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। श्री उइके ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा उनके जीवन में पुनः सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। इस अवसर पर भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, कृष्णा गायकी, जनपद पंचायत अध्यक्ष भैयालाल इरपाचे, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुनील भलावी, अनिल उइके, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सोनू सुनील भलावी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ग्राम तिरमहू में 10 वर्ष पुरानी विद्युत समस्या का हुआ समाधान

बैतूल। वितरण केंद्र आमला ग्रामीण अंतर्गत ग्राम तिरमहू में विद्युत विभाग द्वारा लंबे समय से चली आ रही विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान जनकल्याण शिविर के दौरान किया गया। विभाग द्वारा गांव में विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के लिए विभिन्न सुधार कार्य किए गए। ग्राम में 11 केवी लाइन के 10 तथा एलटी लाइन के 73 नए सीमेंट पोल स्थापित किए गए। साथ ही झूलती हुई एलटी लाइनों को कसकर मानक ऊंचाई पर किया गया। खेतों में स्थित दो तिरछे डीटीआर/डीपी को सीधा कर उनके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हुई। किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी निराकरण किया गया। श्री रघुनाथ पूरन के खेत में नीचे झूलते तारों को सुरक्षित करने के लिए 5 पोल लगाए गए। श्री मनोज ठाकरे के खेत में 11 केवी लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर करने के लिए 2 नए पोल स्थापित किए गए। वहीं श्री तरुण पंडाग्रे के खेत में तिरछे डीटीआर/डीपी को सीधा किया गया। पंचायत भवन एवं स्कूल मोहल्ले में नीचे झूल रही केबल को ऊंचा करने के लिए 2 मिड-स्पान पोल लगाए गए, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ग्राम में आयोजित शिविर के दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी दी गई तथा सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बिजली बचत, विद्युत चोरी रोकथाम, विभागीय मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग तथा समय पर बिजली बिल जमा करने के संबंध में भी जागरूक किया गया।

युवा कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर किया प्रदर्शन

बैतूल। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सोमवार को जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय सरदार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर आग बुझाने और प्रदर्शन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपने विरोध पर डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय सरदार यादव ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन जैसी वरिष्ठ और ईमानदार नेत्री का राज्यसभा नामांकन कथित रूप से तकनीकी आधारों पर निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता खो चुका है और भाजपा सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष की आवाज को दबाने और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। युवा कांग्रेस नेताओं संजय सरदार यादव और प्रीतेश गंगारे ने संयुक्त रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग अब स्वतंत्र संस्था की बजाय भाजपा के कठपुतली विभाग की तरह कार्य करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की बढ़ती राजनीतिक ताकत से घबराकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। युवा कांग्रेस संगठन प्रभारी लवलेश बब्बा राठौर और प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने ने भी निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तो युवा कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा कांग्रेस सडक़ से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस संगठन प्रभारी लवलेश बब्बा राठौर, हर्षवर्धन धोटे, मनोज आहूजा, राजू चौबे, अनूप जायसवाल, प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने, सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ट्राइडेंट बुधनी कंपनी के लिए रोजगार मेला 18 जून को

बैतूल। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइडेंट बुधनी कंपनी द्वारा 18 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य ने बताया कि रोजगार मेले के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की आयु 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा अथवा स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई गोविंदपुरा, भोपाल में अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून को

बैतूल। राष्ट्रीय पल्स-पोलियों अभियान 28 जून को आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि आयोजन के प्रथम दिवस पोलियो बूथ पर तथा दूसरे एवं तीसरे दिवस पल्स पोलियो दल घर-घर जाकर छूटे हुये बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने बताया कि विगत 15 वर्षो से भारत वर्ष पोलियो मुक्त है, लेकिन विश्व के कुछ भागों में और हमारे पडोसी देशों में अभी भी वाईल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण जारी है जिससे आयातित मामलों का खतरा बना रहता है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय : डागा

बैतूल। लोकतंत्र, किसानों, पेयजल व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बैतूल गंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। श्री डागा ने कहा कि जिस आधार पर नामांकन निरस्त किया गया, उसने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस निजी परिवाद का हवाला दिया गया, उसमें मीनाक्षी नटराजन अभियुक्त नहीं प्रतिवादी थीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33ए और फॉर्म-26 की भावना के अनुरूप नामांकन निरस्त करने का आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे विवादित आधारों पर नामांकन खारिज किए जाएंगे तो भविष्य में मनमानी और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। श्री डागा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन जी जैसी साफ-सुथरी छवि, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनसेवा के लिए समर्पित

नेता को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। पत्रकार वार्ता में संगठन महासचिव ब्रजभूषण पांडे, जिला प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर, विजय पारधी सोशल मीडिया प्रभारी अनूप जैसवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, जिला सचिव अभय वर्मा उपस्थित थे।

खाद संकट से परेशान किसान- इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले में ई-टोकन सिस्टम पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। किसान खाद के लिए परेशान हैं और दूर-दूर से किसी प्रकार खाद खरीदने पहुंच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई किसानों को उनके ब्लॉक से दूर स्थित दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाना पड़ रहा है। पहले से महंगी खाद के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। साथ ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मेडिकल कॉलेज की भूमि को लेकर जताई चिंता - पत्रकार वार्ता में पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठाया गया। निलय विनोद डागा ने कहा कि कांग्रेस की लंबे समय से मांग रही है कि मेडिकल कॉलेज को सरकारी किया जाए। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि में ऐसे लोगों को भी सरकार द्वारा पट्टे दिए गए हैं, जिन्होंने वहां अपने मकान बना रखे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि जिन लोगों को पट्टे दिए गए हैं या जिनके मकान वहां बने हुए हैं, उनकी भूमि किसी भी कीमत पर अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए।

महंगाई से आम जनता त्रस्त - कांग्रेस ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा। निलय विनोद डागा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी में घरेलू गैस सिलेंडर 877 रुपये था, जो जून में बढ़कर 966 रुपये हो गया। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर फरवरी के 1740 रुपये से बढ़कर जून में 3113 रुपये तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत फरवरी में 107.48 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर जून में 115.05 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 92.83 रुपये से बढ़कर 100.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर नाराजगी - कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश और मध्यप्रदेश में नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं अंतिम समय में निरस्त या स्थगित की जा रही हैं, जिससे युवाओं में हताशा का माहौल बन रहा है। उन्होंने भोपाल में आयोजित जेल प्रहरी परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठाने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि हजारों रुपये खर्च कर परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले युवाओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

भारतीय जहाज पर हमले को बताया चिंताजनक - निलय विनोद डागा ने ओमान के निकट भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हुए हमले को अत्यंत चिंताजनक और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप अब सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस बयान के बाद कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी, केंद्र सरकार की विदेश नीति और उसके दावों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में 18 जून को आयोजित होने वाले 'आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण 'कार्यक्रम की तैयारियों का शनिवार को कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे एवं पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्थान के प्रतिनिधि , अपर कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे सहित व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि के आगमन, ग्रीन रूम, मंच व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, डी निर्माण, सेक्टर निर्माण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा अधिकारियों ने राष्ट्रपति के आगमन एवं आवागमन मार्गों (रूट्स) का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे एवं पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रोटोकॉल के अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया जा सके।

नवांकुर अभियान: केसला के कासदा रैयत में सीड बॉल निर्माण एवं वृक्षारोपण, ग्रामीणों में दिखा उत्साह

नर्मदापुरम (निप्र)। नवांकुर अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकासखंड केसला के ग्राम कासदा रैयत में वृहद सीड बॉल निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नीम, करंज, जामुन और महुआ के बीजों को मिट्टी व जैविक खाद के साथ मिलाकर 130 से अधिक सीड बॉल तैयार किए। इन सीड बॉल का उपयोग वर्षा ऋतु में अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम इटारसी श्री नीलेश शर्मा स्वयं शामिल हुए। उन्होंने सीड बॉल निर्माण और पौधारोपण में श्रमदान कर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत केसला की सीईओ श्रीमती सुमन खातरकर, ग्राम पंचायत चौकीपुरा के सरपंच सहित 32 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधे रोपे और सीड बॉल बनाए। स्व-सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से पूरे आयोजन में विशेष उत्साह देखने को मिला। यह कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायी उदाहरण बना।

■ अनुगूंज राज्य स्तरीय कानूनी साक्षरता शिविर

शिविर में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों की समस्याओं पर हुई सार्थक चर्चा

विधिक अधिकारों, डिजिटल सुविधाओं और सामाजिक समावेशन पर किया गया जागरूक, प्रतिभागियों की

विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शेख सलीम के मार्गदर्शन में शनिवार 13 जून को जिला न्यायालय विदिशा के वी.सी. रूम में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों के लिए 'अनुगूंज राज्य स्तरीय कानूनी साक्षरता शिविर' का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री शेख सलीम, विशेष न्यायाधीश श्री जी.सी. शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदाधिकारी तथा अन्य न्यायिक एवं विधिक अधिकारी उपस्थित रहे।

शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर श्री विवेक रूसिया तथा न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विकसित विशेष मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस एप के माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं, मध्यस्थता सेवाओं का लाभ ले सकते हैं तथा अपनी संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) के माध्यम से भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल न्याय तक समान और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिविर में प्रतिभागियों को निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक अधिकारों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागियों ने अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को खुलकर साझा किया। प्रतिभागियों ने बताया कि जिला अस्पतालों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र समय पर और नियमानुसार नहीं बन पाते, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं। प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि अधिकांश शासकीय कार्यालयों में संकेत भाषा जानने वाले अनुवादकों की अनुपलब्धता के कारण शिकायतें दर्ज कराने तथा अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। कई प्रतिभागियों ने सामाजिक स्तर पर उपहास और भेदभाव का सामना करने की पीड़ा भी साझा की। वहीं, विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को साइन लैंग्वेज का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में भी बाधाएं सामने आने की बात रखी गई। प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इन मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक पत्राचार एवं कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने का भरोसा भी दिलाया गया।

850 ग्राम वजन की नवजात को मिला नया जीवन, 72 दिन के उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी

बैतूल (निप्र)। जिला अस्पताल बैतूल स्थित विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में गंभीर एवं कम वजन वाले नवजात शिशुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। एसएनसीयू यूनिट के प्रभावी संचालन और विशेषज्ञ चिकित्सकीय देखभाल के कारण कई नवजातों को नया जीवन मिल रहा है।

इसी क्रम में विकासखंड चिचोली के ग्राम हरनिया निवासी श्रीमती रामकला के यहां 27 मार्च 2026 को घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के समय बच्ची का वजन मात्र 850 ग्राम था तथा उसका गर्भकाल 28 सप्ताह का था। अत्यंत कम वजन और समय से पूर्व जन्म होने के कारण नवजात को उसी दिन जिला अस्पताल बैतूल के एसएनसीयू में भर्ती किया गया।

एसएनसीयू के प्रभारी डॉ. आशीष ठाकुर ने बताया कि भर्ती के दौरान नवजात की स्थिति गंभीर थी। चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की सतत निगरानी में बच्ची को 2 दिनों तक सीपीएपी श्वसन सहायता तथा 10 दिनों तक ऑक्सीजन सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा संक्रमण की आशंका को देखते हुए आवश्यक उपचार एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया। उपचार के दौरान नवजात की नियमित मॉनिटरिंग और विशेष देखभाल की गई। लगातार 72 दिनों तक चले उपचार और देखभाल के बाद बच्ची के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

डिस्चार्ज के समय उसका वजन बढ़कर 1.27 किलोग्राम हो गया और उसे स्वस्थ अवस्था में घर भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार यदि यही उपचार किसी निजी अस्पताल में कराया जाता, तो नवजात के माता-पिता को लगभग 5 से 7 लाख रुपये तक का खर्च वहन करना पड़ सकता था। जिला अस्पताल बैतूल के एसएनसीयू में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी तथा आवश्यक उपचार की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इससे परिवार को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलने के साथ भारी आर्थिक राहत भी मिली।

मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 की समीक्षा बैठक संपन्न

● प्रेक्षक अभय वर्मा ने दिए शुद्ध एवं त्रुटिरहित सूची तैयार करने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। स्थानीय निर्वाचन के अंतर्गत वार्षिक मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 के कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा बैठक प्रेक्षक श्री अभय वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। निर्वाचन प्रेक्षक श्री अभय वर्मा ने जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रेक्षक श्री वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता के लिए सटीक एवं विश्वसनीय मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएं तथा अपात्र अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को नियमानुसार संशोधित किया जाए। साथ ही सभी दावों एवं आपत्तियों का समयबद्ध और निष्पक्ष निराकरण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे पुनरीक्षण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की तथा प्रगति से अवगत कराया। बैठक के अंत में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने प्रेक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किए जाएं ताकि आगामी स्थानीय निर्वाचन की तैयारियां सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सकें। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर , जिला पंचायत सीईओ श्री ओ.पी. सनोडिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीपाश्री गुप्ता, तहसीलदार शहरी एवं ग्रामीण, जनपद पंचायत विदिशा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरपालिका परिषद विदिशा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के विभिन्न विकासखंडों से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगर निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे।

कॉलेज की फीस दो किस्तों में जमा कर सकते हैं विद्यार्थी

सीहोर (निप्र)। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉ रोहिताश्व कुमार शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का शिक्षण शुल्क दो किस्तों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र-छात्राओं पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने बताया कि एमपी ऑनलाइन काउंटर्स पर विद्यार्थियों को आनलाइन माध्यम से एक साथ पूर्ण शुल्क जमा करने के लिये कहा जा रहा है, जिससे विद्यार्थी असमंजस में पड़ रहे हैं। विद्यार्थी दो किस्तों में अपनी फीस जमा कर सकते हैं।

कलेक्टर डॉ सोनवणे से मिले राज्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी

बैतूल (निप्र)। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 दिवसीय ग्राम भ्रमण पर आए 15 राज्य सेवा अधिकारियों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे से भेंट की। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने अधिकारियों से ग्राम भ्रमण के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभवों के संबंध में चर्चा की।अधिकारियों ने अपने भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों की जानकारी साझा की। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित नहीं है , बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए कार्य करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ग्राम भ्रमण से प्राप्त अनुभव एक अधिकारी को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं और बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने कार्यकाल में संवेदनशीलता, ईमानदारी और जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनके निराकरण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करें।

श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय की आवाज को मिली एक नई पहचान

अनुगूंज पहल के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुगूंज पहल के अंतर्गत श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय के लिए जिला न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने जिला स्तरीय शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी संबंधितों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि 'अनुगूंज' श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय की आवाज को एक नई पहचान दिलाने की पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्ति की आवाज को एक ऐसा मंच प्रदान किया जायेगा, जिसके माध्यम से उसकी समस्या एवं भावनाएं व्यक्त की जा सकें तथा उसकी समस्याओं का निराकरण भी संभव हो सकें। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संकेतवाणी एप बनाया गया है, जिसमें कोई भी श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्ति संकेत भाषा में वीडियो बनाकर अपनी समस्या बता सकता है, जिसका अनुवाद कर उसकी समस्या को जानने एवं निराकरण का कार्य विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। यह एक नई पहल है, जो श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभकारी है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की गई तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संचालित विधिक सेवा संस्थाओं के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्न जाने और निराकरण भी किया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मण्डलोई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश श्री एम.के. वर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अनिल पारे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, श्रवण एवं वाक बाधित प्रतिभागीगण, स्वास्थ्य विभाग एवं डीआईसी की विशेष टीम, एनआईएमएचआर की टीम, सामाजिक न्याय विभाग की टीम, एनजीओ के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पैनल एवं अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, खण्डपीठ सदस्य, विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण, पैरालीगल वालेन्टियर्स आदि उपस्थित रहे।

सीहोर जिले के 196 तीर्थ यात्री वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा के लिए होंगे रवाना

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के 196 तीर्थ यात्रियों का दल वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा के लिए 13 जून की रात सीहोर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से रवाना होगा। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तीर्थ यात्रियों की सहायता, मार्गदर्शन एवं समन्वय के लिए चार पर्यवेक्षक भी उनके साथ यात्रा में शामिल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

सिरोंज जनकल्याण शिविर नागरिकों की उम्मीदों पर खरा, दो दिनों में 429 आवेदनों का त्वरित निराकरण

जनकल्याण शिविरों ने जीता जनता का विश्वास, समस्याओं के त्वरित समाधान से लौट रहे संतुष्ट नागरिक

विदिशा (निप्र)। प्रदेशव्यापी जनकल्याण अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में आयोजित किए जा रहे जनकल्याण शिविर आमजन के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बनते जा रहे हैं। शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंच रहे हैं।

समस्याओं के मौके पर समाधान और आवश्यक मार्गदर्शन मिलने से आवेदकों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के संयुक्त तत्वावधान में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जहां अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। शिविरों में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा, विद्युत, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जबकि अन्य मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जनकल्याण शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से समय और संसाधनों की बचत हो रही है। इससे शासन और प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

शिविरों में पहुंचने वाले नागरिकों ने शासन और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जनकल्याण शिविर अब केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और सहभागिता का सशक्त मंच बनकर उभर रहे हैं।

जिले में निरंतर आयोजित किए जा रहे ये शिविर शासन की जनकल्याणकारी सोच को धरातल पर साकार करने के साथ-साथ सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

जनकल्याण शिविरों के माध्यम से आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सिरोंज विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित जनकल्याण शिविर के दुसरे दिन ग्राम भौंरा निवासी कृषक श्री बसोड़ा पुत्र श्री बारेलाल अहिरवार अपनी कृषि भूमि के सीमांकन संबंधी आवेदन को लेकर जनकल्याण शिविर में पहुंचे थे। कृषक ने बताया कि उनकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 111/5, रकबा 1.679 हेक्टेयर की सही चतुर्सीमाएं स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें भूमि संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर दिया था। एसडीएम श्री हरिशंकर विश्वकर्मा की नजर अचानक आवेदक पर पड़ी। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सीधे राजस्व काउंटर पर पहुंचकर आवेदक से आत्मीयता के साथ चर्चा की और पूछा, ' काय दादा, काये को आए' इसके बाद उन्होंने आवेदक की पूरी समस्या गंभीरता से सुनी। आवेदक का वृत्तांत सुनने के पश्चात एसडीएम श्री विश्वकर्मा ने मौके पर ही तहसीलदार को लिखित निर्देश जारी किए और सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदक को आश्वस्त करते हुए कहा कि 'कल आपकी जमीन का सीमांकन कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

लोन वुल्फ अटैक मामले में गिरफ्तार

भोपाल के खालिद सैफुल्ला का पाकिस्तान से निकला कनेक्शन, अफगानिस्तान में थी ट्रेनिंग

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने रविवार को एक बड़े अंतर-राज्यीय कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। एटीएस ने इस खुफिया नेटवर्क से जुड़े तीसरे मुख्य संदिग्ध मोहम्मद शाकिर (34) को राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। यह नेटवर्क कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया जा रहा था।

तीन राज्यों से जुड़े हैं नेटवर्क के तार

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह नेटवर्क बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। शाकिर की गिरफ्तारी से ठीक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (नानौता) से नईम अब्दुल्ला कुरैशी (38) को दबोचा गया था, जबकि एक दिन पहले ही भोपाल के काजी कैंप इलाके से मोहम्मद फराज (35) की गिरफ्तारी हुई थी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह एक बंद ऑनलाइन ग्रुप था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का ब्रेनवॉश करना और उन्हें 'लोन वुल्फ' यानी अकेले हमला करने की शैली के हमलों के लिए तैयार करना था।

अफगानिस्तान जाकर हथियार चलाने की थी ट्रेनिंग की तैयारी

गिरफ्तार आरोपियों में से भोपाल का रहने वाला मोहम्मद फराज एक ग्रेजुएट है और स्थानीय होम्योपैथिक क्लिनिक में काम करता था। पूछताछ में सामने आया है कि फराज पासपोर्ट बनवाकर हथियार और आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान जाने की फिराक में था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे 'खालिद सैफुल्लाह' का कोडनेम (उपनाम) भी दे रखा था।

- मोहम्मद शाकिर (34 वर्ष)राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर इंटर-स्टेट नेटवर्क का सक्रिय सदस्य, रविवार को अरेस्ट, 20 जून तक एटीएस कस्टडी
- मोहम्मद फराज (35 वर्ष)काजी कैंप, भोपाल कोडनेम 'खालिद सैफुल्लाह', अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था, 16 जून तक एटीएस कस्टडी
- नईम अब्दुल्ला कुरैशी (38 वर्ष) नानौता, सहारनपुर (यूपी) ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क का अहम हिस्सा, शुक्रवार को अरेस्ट, 16 जून तक एटीएस कस्टडी

कोर्ट ने एटीएस रिमांड पर भेजा

एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक और संदिग्ध की पहचान की जा चुकी है, जिसकी तलाश में दूसरे राज्यों में छापेमारी जारी है। अदालत ने आरोपी फराज और कुरैशी को 16 जून तक, जबकि नवीनतम गिरफ्तार आरोपी शाकिर को 20 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। एटीएस अब इनसे कड़ाई से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगा रही है।

दोस्ती की आड़ में दोस्त की बहन के साथ घिनौना काम

रेप के बाद कराया अबॉर्शन, धर्मांतरण करवाकर किया निकाह

रतलाम (नप्र)। मध्य प्रदेश के रतलाम में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ ये सब कुछ उसके भाई के दोस्त ने किया है। उसने बार-बार पीड़िता के साथ रेप किया। साथ ही दो बार उसका गर्भपात करवाया। इसके बाद धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह किया है। अब उसका एक बच्चा है लेकिन पीड़िता के साथ आए दिन मारपीट करता है।

डीडी नगर क्षेत्र में रहती है पीड़िता

दरअसल, 19 वर्षीय पीड़िता रतलाम के डीडी नगर क्षेत्र में रहती है। उसने अपने भाई के दोस्त समीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। आरोपी है कि करीब तीन साल पहले आरोपी समीर ने उसके साथ रेप किया था। फिर चाकू की नोक पर उसने बार-बार ऐसा किया है।

अबॉर्शन करवाया- आरोपी ने पीड़िता को दो बार प्रेग्नेंट किया। साथ ही उसका अबॉर्शन भी करवाया। आरोपी समीर रामरहीम नगर का रहने वाला है। पीड़िता के भाई से दोस्ती की वजह से उसका घर आना जाना लगा रहता था। इसी पहचान की वजह से आरोपी ने पीड़िता से नजदीकी बढ़ाई।

अपने घर ले जाकर किया दुष्कर्म- पीड़िता के साथ आरोपी ने पहली बार 2023 में दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता 11वीं की छात्रा थी। पहले आरोपी ने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अपने रामरहीम नगर स्थित घर ले गया, जहां उसके साथ गलत किया।

अबॉर्शन करवा दिया- इस दौरान पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई। यह पता चलते ही समीर ने उसे गर्भपात की गोलियां दे दीं। साथ ही पीड़िता को चाकू दिखाकर धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार दूंगा। डर से युवती चुप रही। इस नाम पर समीर उसके साथ संबंध बनाता रहा।

स्कूटी से 12वीं टॉपर के घर पहुंच गए मोहन यादव

● हौंसले की बुलंदी से हर मंजिल होती है आसान: मुख्यमंत्री ● प्रतिभावान बेटी की पढ़ाई में गरीबी नहीं बनेगी कभी बाधा

भीमनगर तंग गलियों में सीएम को देखकर अचंभित हुए लोग, चांदनी की फैमिली के साथ ली सेल्फी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि परिवार में गरीबी, कठिनाई के बावजूद हौंसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। विषम परिस्थितियों में भी कुमारी चांदनी ने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से जो उपलब्धि हासिल की है, वह प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एमपी बोर्ड 12वीं की टॉपर कुमारी चांदनी विश्वकर्मा से मिलने ई-स्कूटर से विधानसभा के निकट स्थित भीम नगर बस्ती पहुंचे। ई-स्कूटर पर सवार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं हेलमेट पहना और उनके साथ ई-स्कूटर पर पीछे बैठे विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने भी हेलमेट लगाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने, सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रभावशीलता के संबंध में स्थानीय निवासियों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुमारी चांदनी और उनके परिजन से आत्मीय भेंट की और परिजन के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चांदनी की उत्कृष्ट सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रतिभावान बेटी की पढ़ाई में गरीबी कभी बाधा नहीं बनेगी। कुमारी चांदनी को शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलाकर दिया ईंधन बचाने का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वैश्विक ईंधन संकट के बीच भीम नगर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर से पहुंचे। उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचाने और पर्यावरण-संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रहित में सबसे पहले अपना कारकेड घटाने का निर्णय लिया था। उनकी पहल पर कारकेड में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को शामिल किया गया है।

नियम विरुद्ध रजिस्टर्ड हुईं 2440 बसें

इंदौर-नीमच सबसे अव्वल, एसोसिएशन ने सीएम से की अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में परिवहन अधिकारियों द्वारा बस बॉडी के टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के बिना 2440 नई बसों के पंजीयन का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पत्र से यह साफ हो गया है कि 1 सितंबर 2025 से नियम लागू होने के बाद भी प्रदेश के 52 परिवहन कार्यालयों में नियमों ताक पर रखकर बसों का पंजीयन किया गया। इनमें 1487 यात्री बसें, 745 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बस, 141 स्कूल बस और 67 प्राइवेट सर्विस व्हीकल शामिल हैं।

एसोसिएशन ने कहा- बस मालिक नहीं, अधिकारी हैं दोषी- मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में साफ कहा है कि बस मालिकों को प्रचलित कानूनों की जानकारी नहीं होती, इसलिए वे अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठे। उनकी बसों का पंजीयन निरस्त करना उचित नहीं होगा। लेकिन परिवहन अधिकारी, जिनका काम ही नियमों की पालना सुनिश्चित करना है, उन्होंने जानबूझकर 1 सितंबर 2025 से लागू नियमों की अवहेलना की। संघ का आरोप है कि इन अधिकारियों ने बस डीलरों को अवांछित लाभ पहुंचाने के लिए यह कुकर्म किया, जो स्पष्ट रूप से पद के दुरुपयोग का मामला है।

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग- एसोसिएशन ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यह मामला केवल नियमों की अनदेखी का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आने वाला है। संघ ने मांग की है कि सभी दोषी परिवहन अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए विधिवत बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने पहले ही अपने पत्र में इन पंजीयनों को नियमविरुद्ध बताते हुए सभी जिला परिवहन अधिकारियों को 15 दिनों में रिपोर्ट देने और पंजीयन रद्द करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब बस संघ ने अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की मांग कर मामले को और गर्म कर दिया है।

पहले क्या नियम था? (1 सितंबर 2025 से पहले)- 1 सितंबर 2025 से पहले, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47(1)(1)(जी) के तहत, बस चेसिस पर अलग से बॉडी बनाने वाले (बॉडी बिल्डर) को सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होता था। इसे फॉर्म 22बी कहा जाता था। इसी फॉर्म 22बी के आधार पर बसों का पंजीयन हो जाता था, बिना किसी तीसरी पार्टी से प्रमाणन कराए। यानी बॉडी बिल्डर खुद ही प्रमाणित करता था कि बॉडी सही है।

एमपी में तबादलों की समय-सीमा बढ़ सकती है

आज खत्म हो रही है ट्रांसफर की टाइम लिमिट, कई विभाग नहीं निकाल पाए आदेश

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में तबादलों के लिए तय की गई 15 जून की समय-सीमा खत्म हो गई है, लेकिन ज्यादातर विभाग अब तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार तबादलों की अवधि एक हफ्ते तक बढ़ा सकती है। इस संबंध में आदेश सोमवार को जारी होने की संभावना है।

सिर्फ कुछ विभागों ने जारी किए आदेश- सरकार ने 1 जून से 15 जून तक तबादले करने की अनुमति दी थी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम और लोक निर्माण विभाग जैसे कुछ विभागों ने ही तबादला आदेश जारी किए। वहीं कई बड़े विभाग अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा था- समय नहीं बढ़ेगा- 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को 15 जून तक तबादले करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी लगातार कह रहे थे कि तबादलों की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और सभी विभाग समय पर प्रक्रिया पूरी करें। इसके बावजूद कई विभाग तय समय में काम पूरा नहीं कर सके।

- **शिक्षा, पंचायत और राजस्व विभाग पीछे-** सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग में अभी भी तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। इन विभागों की तय की गई टाइमलाइन 15 जून के बाद तक जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग तो जुलाई तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने की अलग व्यवस्था भी बना चुका है।
- **सरकार बढ़ा सकती है अवधि-** कई विभागों में प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण अब सामान्य प्रशासन विभाग तबादलों की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने पर सहमति बन गई है। यदि आदेश जारी होते हैं तो विभागों को लंबित तबादला प्रस्तावों पर फैसला लेने के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे।

मंत्री विभागों में जमे रहे, अफसर सूची तैयार करते रहे

उधर तबादला अवधि के अंतिम दिन होने के चलते आज मोहन कैबिनेट के अधिकांश मंत्री अपने विभागों में जमे रहे और अधिकारी तबादला सूची में नाम जोड़ने और काटने में जुटे रहे। जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को आज बीजेपी दफ्तर पहुंचना था लेकिन तबादला सूची के चलते वे बीजेपी

सीधी जिले के थाना प्रभारी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

विवाद सुलझाने पहुंचे थे गांव

सीधी (नप्र)। मध्य प्रदेश सीधी जिले में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ है। विवाद सुलझाने गए कमर्जी थाना प्रभारी पर लोगों ने कुल्हाड़ी और हंसिए से हमला किया है। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती- इस हमले में कमर्जी थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, पटपरा सरपंच के घर से लगभग 100 मीटर आगे पटेल परिवार के द्वार के पास सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। मार्ग बाधित होने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रास्ता खुलवाने की कार्रवाई शुरू की।

आरोपियों ने कर दिया कुल्हाड़ी से हमला- बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद दिनेश पटेल उर्फ गुंठी, उसका भाई सुनील पटेल, पुत्र विनय पटेल उर्फ पंडित, प्रीतम पटेल उर्फ दुली, रितेश पटेल उर्फ सिंटू सहित परिवार के अन्य सदस्य और महिलाएं मौजूद थीं। आरोप है कि पुलिस द्वारा अवरोध हटाने की कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी और पुलिस दल पर धारदार हथियारों और अन्य साधनों से हमला कर दिया गया।

थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल- हमले में थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल डायल-112 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

एम.पी. ट्रांसको में हुई सब स्टेशनों के संचालन एवं सुरक्षा से संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सब स्टेशन संचालन एवं सुरक्षा से संबंधित व्यापक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन जिले के नागदा, धार जिले के बदनावर व राजगढ़ टेस्टिंग डिवीज़न मुख्यालयों मे प्रशिक्षण कार्यशाला अधीक्षण अभियंता श्री शेखर फटाले के मार्गदर्शन में हुई। जिनमें सब स्टेशन मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन कार्यों के दौरान अपनाई जाने वाली आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाओं को बिंदुवार समझाया गया एवं कार्यस्थल पर लापरवाही रोकने के महत्व पर विशेष जोर देते हुए दुर्घटनाओं से बचाव के लिये व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी, जिससे कार्मिकों एवं उपकरणों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षित कार्यशैली से कराया गया अवगत- प्रशिक्षण में श्री फटाले ने एम.पी. ट्रांसको की जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) एवं सेफ्टी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया। प्रतिभागियों को सुरक्षित कार्य पद्धतियों, सुरक्षा उपकरणों के उपयोग तथा निर्बाध एवं सुरक्षित विद्युत पारेषण बनाए रखने के लिये समन्वित टीमवर्क के रूप में कार्य करने के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यशालाओं में क्षेत्र के अभियंताओं एवं तकनीकी स्टाफ ने सक्रिय सहभागिता की।

चूक के जिम्मेदार कौन?

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की चूक ने पूरे परिणाम का स्वाहा कर दिया। प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसमें आपराधिक रिकॉर्ड को गोपनीय रखा गया था। अब कांग्रेस के दिग्गज इस पर मंथन कर रहे हैं कि यह भूल हुई या भूल करवाई गई। खैर, हम तह तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन गलियारों की चर्चा है कि कांग्रेस की लीगल टीम के एक धुरंधर ने अपने पुराने जख्मों से कुछ नहीं सीखा। मीनाक्षी जी का नामांकन बच सकता था, बशर्ते उसे भरने वाले खुद अनुभवी न होते। ये वही कानून के ज्ञाता हैं, जो नगर निगम भोपाल चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बनने का सपना सजाकर नामांकन भरने गए थे। तब उनकी खुशी का ठिकाना न था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने जैसे ही उनका पर्चा खारिज किया, पार्षद बनने की हसरत उसी पल दम तोड़ गई। विडंबना देखिए, मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में वही फ़ाइनल टच देने वाले महोदय शामिल थे। जब खुद का नामांकन नहीं बचा पाए, तो नटराजन जी का कैसे बचता?

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

पूर्व मंत्री का अनुसरण

एक वर्तमान मंत्री का व्यवहार उनके समर्थकों को रास नहीं आ रहा। वे पूर्व के एक गालीबाज मंत्री की राह पर निकल पड़े हैं। स्थानीय भाषा की आड़ में समर्थकों को सार्वजनिक रूप से अपशब्द बोलना अब उनकी आदत बन चुकी है। शिवराज युग के उस चर्चित मंत्री की याद ताजा हो रही है, जो अपशब्दों को ही अपनी पहचान बना चुके थे. हालांकि मंत्री की साख का ग्राफ काम नहीं हुआ है.

ईएनसी की विदाई-ढीलापन पड़ा भारी

काम के बढ़ते दबाव के बीच एक बड़े निर्माण महकमे के ईएनसी पर गाज गिरी है। विभाग में तालमेल बिठाने में नाकाम रहे अधिकारी का ढीला रवैया मंत्री और पीएस की नजरों में खटक गया। अंतत: ईएनसी को हटाकर मंत्रीजी के पसंदीदा जबलपुर के अफसर को कमान सौंप दी गई है। स्पष्ट है, अब विभाग में काम का प्रेशर बढ़ाने से नहीं, बल्कि परिणाम से कम होगा।

'12' का गणित और कुंभ का जुड़ाव

प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के बेदाग कार्यकाल का जश्न भाजपा की हर इकाई में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को एक अनोखे आध्यात्मिक रंग में रंगा। उन्होंने 12 वर्ष और 12 माह के चक्र को मध्य प्रदेश के कुंभ से जोड़कर ऐसी व्याख्या की कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। विकास के इस महाकुंभ में उन्होंने मोदी युग को एक युगपुरुष की सिद्धि करार दिया।

एसीएस का 'स्वछंद' राज

अपर मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी फिर विवादों में हैं। आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक संस्था के मुखिया की नकेल कस दी है। नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करने वाले इस अधिकारी के खिलाफ अब संस्था के मुखिया ने मंत्रालय की पांचवीं मंजिल तक गुहार लगा दी है। देखना यह है कि क्या यह पत्र कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेगा या पत्र धूल फांकता रह जाएगा. ?